▪ RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 331 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 01-07-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

2 कांग्रेस राजनीति के अपराधीकरण का पर्याय बनती जा रही है : नितिन नवीन

6 आखिरी उपाय बनाम पर्यावरण - अनुकूल दृष्टिकोण

7 ऑटिज्म बीमारी नहीं, समझ और अपनापन चाहिए : ईशा सिंह

फर्स्ट टेक

फोन नंबर साझा किए बगैर चैट करने के लिए व्हाट्सएप लाएगी नया फीचर

नई दिल्ली/भाषा। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मंच व्हाट्सएप ने 'यूजरनेम' फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इस फीचर के जरिये उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना एक-दूसरे से बातचीत (चैट) कर सकेंगे। कंपनी ने यूजरनेम के लिए अग्रिम आरक्षण शुरू कर दिया है। यह फीचर इस वर्ष के अंत में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, ''इस सप्ताह से आप अपना यूजरनेम आरक्षित कर सकते हैं, जिसका उपयोग इस वर्ष के अंत में फीचर शुरू होने पर किया जा सकेगा।'' कंपनी के अनुसार, इस सुविधा का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखना है। खासकर ग्रुप चैट या नए लोगों से संपर्क के दौरान अब मोबाइल नंबर साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बीजिंग में संस्कृत और सिद्धम लिपि पर प्रदर्शनी आयोजित

बीजिंग/भाषा। बीजिंग में संस्कृत सुलेख और सिद्धम लिपि पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें भारत और चीन की साझा सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित किया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यहां स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि 'प्रांगण में संस्कृत सुलेख' शीर्षक से आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े संस्कृत प्रेमियों की कृतियां प्रदर्शित की गईं। इसका आयोजन बीजिंग स्थित कोर्टयार्ड इंस्टीट्यूट ने किया। दूतावास के अनुसार, यह प्रदर्शनी संस्कृत और सिद्धम लिपि की सुंदरता का उत्सव है, जो भारत और चीन के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को प्रतिबिंबित करती है।

ईरान युद्ध खत्म करने के समझौते पर बैठक के लिए अमेरिकी दूत कतर पहुंचे

दुबई/एपी। ईरान युद्ध खत्म करने के शुरुआती समझौते को लागू करने के बारे में मध्यस्थों के साथ वार्ता करने के लिए अमेरिका के दो दूत मंगलवार को कतर पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, और उनके (ट्रंप के) दामाद जे. कुशनर का यह दौरा, फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए फिर से खोलने की कोशिशों को लेकर हुई गोलाबारी के बाद हो रहा है।

01-07-2026 सूर्यास्त 6:49 बजे | **02-07-2026** सूर्योदय 5:57 बजे

BSE	NSE
76,478.67	23,865.75
(-249.70)	(-80.50)

सोना	चांदी
14,698 रु.	229,146 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

अंतहीन व्यभिचार

बढ़ रहे रोज दुष्कर्म आज,
बालिग नाबालिग सब शिकार।
हो रहे पतित इंसान यहां,
हर मन के भीतर दुराचार।
क्या कारण है इसका आखिर,
सोचे निज मन में सभी यार।
या तो भीतर इंसान मरा,
या सिस्टम में आया विकार।।

राष्ट्रपति मुर्मू की छात्रों से अपील

केवल किताबों तक सीमित न रहें, अपने आस-पास के माहौल से सीखें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विशाखापत्तनम/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को छात्रों का आह्वान किया कि वे तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए कौशल विकास के उभरते क्षेत्रों के साथ कदम मिलाकर चलें।

राष्ट्रपति मुर्मू ने आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से कहा कि वे केवल किताबों से मिली जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि व्यावहारिक कौशल विकसित करने के लिए अपने आस-पास के परिवेश से भी सीखें। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने समुदाय, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए समाज और देश के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने तेजी से विकसित हो रहे भारत का संदर्भ देते हुए कहा कि देश की विरासत से जुड़े रहने के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय उत्तरी आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ' विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र'का संचालन कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने आदिवासी कल्याण, जन स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और पोषण सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में शैक्षणिक और ज़मीनी स्तर के कामों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये कोशिशें एक समावेशी और विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

राष्ट्राध्यक्ष ने 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना का हवाला देते हुए विश्वास जताया कि आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित अपनी समावेशी और व्यावहारिक शिक्षण पद्धति के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनजातीय समुदायों के सदस्यों को आधुनिक शिक्षा के लाभ से जोड़ने से स्थानीय युवा देश के समावेशी विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पर कई विशेष ज़िम्मेदारियां हैं और उम्मीद है कि यह आदिवासी समाज में आत्मविश्वास, नेतृत्व और नीति-निर्माण की क्षमताएं विकसित करने का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से स्थापित संस्थानों का यह कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और वन अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर काम करें।

भविष्य में युद्ध ज़्यादा एकीकृत और समन्वित सैन्य अभियान केंद्रित होंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सेना प्रमुख के पद से आज सेवानिवृत्त हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में युद्ध अधिक एकीकृत, संयुक्त एवं समन्वित सैन्य अभियान पर केंद्रित होंगे इसलिए सशस्त्र बलों की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए ''साथ मिलकर देखना, साथ मिलकर निर्णय लेना और साथ मिलकर कार्रवाई करना।''

वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल द्विवेदी 40 साल से अधिक की सेवा के बाद मंगलवार को सेनाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 'साउथ ब्लॉक' के लॉन में आयोजित एक औपचारिक विदाई समारोह में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया किया।

इस कार्यक्रम से इतर जनरल द्विवेदी ने मीडियाकर्मियों से कहा, ''आज, जब मैं सेनाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हूं तो मुझे अत्यंत कृतज्ञता, गर्व और संतुष्टि महसूस हो रही है।''

जनरल द्विवेदी ने जून 2024 में 30वें सेना प्रमुख का पद संभाला था। उन्होंने कहा, ''सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर बहुत शानदार रहा है। चार दशक से अधिक समय तक भारतीय सेना की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।''

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना को अपनी ताकत ''किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है।'' उन्होंने कहा, ''मैं अपनी सेना के वीर नायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।'' विदाई समारोह से पहले जनरल द्विवेदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया और देश के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए वहां पुष्पांजलि अर्पित की।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' उनके कार्यकाल का एक अहम पड़ाव था, जो उभरते सुरक्षा माहौल में सेना की तैयारी, सटीकता और नपे-तुले तरीके से कार्रवाई करने की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने सभी मोर्चों पर ऑपरेशनल तैयारी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी।

मंत्रालय के बयान में कहा गया, ''उनके नेतृत्व में, भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन स्नो लेपर्ड' के तहत उत्तरी सीमाओं पर मज़बूत और सतर्क रुख बनाए रखा और पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ज़िम्मेदारियों को दृढ़ता, संयम और पेशेवर अंदाज़ में निभाया।''

मिट्टी की उर्वरता जांचने के लिए जल्द आएगा मोबाइल ऐप: चौहान

चंडीगढ़/रेवाड़ी/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लाने जा रही है, जिससे वे अपनी मिट्टी की उर्वरता का आकलन कर सकेंगे। उन्होंने उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर भी जोर दिया और जैविक खेती अपनाने की वकालत की ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल में 'खेत बचाओ अभियान' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए चौहान ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग पर चिंता जताई।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक जून को शुरू हुआ यह एक महीने लंबा 'खेत बचाओ अभियान' मंगलवार को संपन्न हुआ। मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसान अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने कहा, '' आप अपने खेत में खड़े होंगे और आपका मोबाइल बताएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कितना उर्वरक डालना चाहिए। हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी से बचाया जा सके।'' किसानों को वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी की जानकारी दी जाती है।

कर्नाटक को 2028 तक मादक पदार्थ मुक्त करने का लक्ष्य : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2028 तक राज्य को मादक पदार्थ से मुक्त बनाना है। उन्होंने जनता, खासकर युवाओं और छात्रों से इस समस्या को खत्म करने में सहयोग करने की अपील की। वह कर्नाटक पुलिस द्वारा आयोजित '' मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

शिवकुमार ने कहा, ''हमारा लक्ष्य 2028 तक कर्नाटक को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त बनाना है। हमने इसे हासिल करने का संकल्प लिया है। अगर जनता, युवा और छात्र सरकार का साथ दें, तो हम इस समस्या को खत्म कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारा संदेश है: नशा छोड़ें, खुशियां चुनें। हमें अपने आदर्श खुद तय करने होंगे। आज हमने जो संकल्प लिया है, वह जीवन भर हमारे साथ रहना चाहिए।''

शिवकुमार ने कहा, ''हमें अपने आस-पास इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। कई लोग हमें बुरी आदतें अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छात्रों और युवाओं को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग ने सरकार को पान मसाला और गुटखा उत्पादों में मादक पदार्थ मिलाने की कथित घटना के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा, ''हमें जानकारी मिली है कि फोन-आधारित डिलीवरी नेटवर्क के जरिए सीधे घरों तक मादक पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं। जो कोई भी पान मसाला या गुटखे में मादक पदार्थ मिलाते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।''

इस अवसर पर कर्नाटक सरकार ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए 'ऑपरेशन राइज' और 'बेड़ा ब्रो' (कहो नहीं भाई) अभियान शुरू किया। इन अभियानों का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों को साथ लेकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री डार ने कहा

सिंधु जल संधि 'वैध, बाध्यकारी और लागू' है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशहाक डार ने मंगलवार को कहा कि उनका देश सिंधु जल संधि को रद्द करने के भारत के फ़ैसले को खारिज करता है और यह ''अब भी वैध, बाध्यकारी और लागू है।'' भारत ने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के साथ 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था। यह कदम फरवरी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

'रेडियो पाकिस्तान' की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डार ने दावा किया कि ''कोई भी पक्ष एकतरफा तौर पर ऐसी संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को स्थगित या समाप्त नहीं कर सकता जिसमें ऐसा कोई प्रावधान न हो।'' उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि केवल पानी के बंटवारे की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ''क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग का एक अहम साधन'' है।

मंत्री ने कहा कि साझा जल-संसाधन ''सहयोग, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर देशों के बीच एक सेतु बने रहने चाहिए, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों का भला हो सके।'' उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को ''सही तौर पर आवंटित'' पानी से वंचित करने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर ''गंभीर परिणाम'' होंगे।

सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीमा-पार बहने वाली नदियों से जुड़े मुद्दों के समाधान और प्रबंधन के उद्देश्य से यह समझौता नौ वर्षों की लंबी वार्ताओं के बाद अस्तित्व में आया था।

भारत ने 26 देशों के साथ गतिशीलता संबंधी समझौते किए हैं : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि भारत ने 26 देशों के साथ 28 प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौतों (एमएमपीए) या उनके समकक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों को लेकर बातचीत जारी है।

विदेश मंत्रालय द्वारा यहां आयोजित मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित करते हुए जयशंकर ने अवैध प्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सुरक्षित आवागमन के मार्ग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गतिशीलता को एक बहुत अहम स्तंभ मानती है और ये साझेदारियां आपसी फायदे, साझा जिम्मेदारी और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता पर आधारित हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि जब ऐसी साझेदारियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो इनसे स्रोत देशों, गंतव्य देशों, नियोक्ताओं, कामगारों और समुदायों के लिए मूल्य का सृजन होता है। उन्होंने कहा, हम सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की जरूरत को भी समझते हैं। अब तक भारत ने 26 देशों के साथ 28 'प्रवास और गतिशीलता साझेदारी समझौते' (एमएमपीए) या उनके समान समझौते किए हैं और कई अन्य समझौतों पर अभी बातचीत चल रही है।

जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवास, शोषणकारी तौर-तरीकों, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा, ये चुनौतियां कानूनी तौर पर आवाजाही के सिस्टम की विश्वसनीयता को कम करती हैं और कमज़ोर लोगों को जोखिम में डाल सकती हैं। इस मंच के लिए कई नीति-निर्माता, क्षेत्र के दिग्गज, नियोक्ता और पेशेवर इकट्ठा हुए हैं।

इस मंच का मकसद विचारों का आदान-प्रदान करने, अनुभवों से सीखने और गतिशीलता के लिए नए तरीकों को खोजने के अवसर देना है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और इसी के तहत, अलग-अलग महाद्वीपों में आबादी के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवोन्मेष उद्योगों को अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमता, ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण और हरित बदलाव भी उन कौशलों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं।

भारत ने यूनान में यूपीआई सेवा शुरू की

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने यूनान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवा शुरू कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने फ्रांस के नीस शहर स्थित प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर गैलेरी लाफायेत में कुछ सप्ताह पहले यूपीआई सेवा शुरू की थी। इससे पहले वर्ष 2024 में पेरिस स्थित एफिल टावर पर भी यूपीआई की शुरुआत की गई थी। गोयल ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि यूनान में यूपीआई शुरू होने के बाद पात्र ग्राहक तुरंत, सुरक्षित एवं निर्बाध तरीके से धन हस्तांतरित कर सकेंगे। साथ ही, लेनदेन की लागत भी पारंपरिक धन हस्तांतरण की तुलना में काफी कम हो जाएगी। मंत्री आधिकारिक यात्रा पर यूनान की राजधानी एथेंस में हैं। उन्होंने कहा, '' एथेंस स्थित यूरोबैंक मुख्यालय में यूरोबैंक-एनआईपीएल साझेदारी के तहत यूपीआई सेवा की शुरुआत का साक्षी बनकर खुशी हुई। इस अवसर पर यूरोबैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फोकियन करावियास और फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज के सीईओ संजय तुगनैत भी मौजूद रहे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कह

न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं, संविधान के प्रति जिम्मेदारी है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायपालिका की सर्वोच्चता के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के प्रति उस जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करने में विफल हों, तब कानून का शासन कायम रहे। उन्होंने कहा, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायिक समीक्षा की यह व्यापक शक्ति भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की नींव है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि सरकार की किसी भी शक्ति के प्रयोग के लिए वैधता और संवैधानिकता अनिवार्य पूर्व शर्त हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने ये विचार सोमवार को स्टॉकहोम में 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' (आईडीईए) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सम्मेलन का विषय था 'कानून के शासन की रक्षा : भारत और स्वीडन के अनुभव।'

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल न्यायालयों की शक्ति नहीं, बल्कि संविधान द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कानून का शासन न तो कोई कल्याणकारी योजना है और न ही कोई आर्थिक नीति। यह अपने आप न लोगों की आजीविका सुनिश्चित करता है, न रोजगार पैदा करता है और न ही गरीबी दूर करता है। लेकिन यह उससे भी अधिक बुनियादी काम करता है-यह सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है।

भारत की विधिक परंपरा का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय न्यायिक चेतना की जड़ें प्राचीन 'धर्म' की अवधारणा में हैं, जो 'साझा कानून' परंपरा से हजारों वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से आए कोई 'औपनिवेशिकोत्तर आयात' नहीं हैं।

गृह मंत्री शाह ने एफसीआरए पोर्टल के नये प्रारूप, ई-ओसीआई कार्ड की शुरूआत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एफसीआरए पोर्टल के नये प्रारूप और ई-ओसीआई कार्ड की शुरूआत की और कहा कि इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी तथा पोर्टल के जरिए विदेशी अंशदान प्राप्त करने वालों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में आवेदनों की संख्या और अंशदान के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कारण ''गलत उद्देश्यों से आने वाले विदेशी अंशदान पर निगरानी बढ़ेगी।''

गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले एफसीआरए फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझा हुआ था और इसमें उचित निगरानी का अभाव था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रणाली को मजबूत किया गया।

गृह मंत्री ने कहा, ''जब नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और तकनीक को स्वीकारने की मानसिकता हो तो सभी प्रकार का शासन ईमानदार लोगों के लिए बहुत सरल हो जाता है, गलत करने वालों पर पैनी निगरानी की व्यवस्था होती है और देश को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।'' उन्होंने कहा कि आज की गई दोनों पहल नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाएंगी और विशेष रूप से एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से अंशदान प्राप्त करने वालों की दिक्कतों का निवारण होगा।

शाह ने कहा कि एफसीआरए पोर्टल का नवीनीकरण, संगठनों के लिए प्रक्रिया को बहुत सरल बना देगा। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में आवेदनों की संख्या और अंशदान के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए कागजी कार्यवाही में कमी लाना और विदेशी अंशदान पर वास्तविक समय पर प्रभावी निगरानी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

शाह ने कहा कि आज शुरू हुई इस प्रणाली के माध्यम से भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और ई-हस्ताक्षर आधारित प्रमाणीकरण और एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) दर्पण बैंक विवरण प्रणाली जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। उन्होंने कहा कि यह सारा डेटा 'मेघराज' (सरकारी क्लाउड) पर होने से डेटा चोरी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके साथ ही, अगले कुछ महीनों में एफसीआरए मोबाइल ऐप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित 'चैटबॉट' और बैंकों के लिए एक विशेष ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असरः मई में सोना आयात वृद्धि में गिरावट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि मई में सोने के आयात वृद्धि में 'काफी गिरावट' आई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कीमती धातु की खपत को कम करने के लिए कई अपील की गई थीं।

रिजर्व बैंक ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा, ''हालांकि, सोने के आयात में वृद्धि पिछले महीने की तुलना में मई, 2026 में काफी कम हो गई है।''

एफएसआर में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत एक ग्राफ से पता चलता है कि मई में सोने का आयात लगभग 12 अरब डॉलर रहा, जो लगातार तीसरे महीने गिरावट का प्रतीक है।

दस मई के आसपास, पश्चिम एशिया संकट के अंत के बारे में कोई निश्चितता नहीं होने के कारण तेल और जिंस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और रुपए पर दबाव पड़ा। कुछ लोगों को आशंका थी कि यह 100 प्रति डॉलर को पार कर जाएगा। ऐसे में मोदी ने नागरिकों से सोने का उपभोग बंद करने की कई बार अपील की।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में सोने के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर जिंस की कीमत में भारी वृद्धि के कारण।

इसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम और सोना मिलकर व्यापार घाटे में आधे से अधिक का योगदान करते हैं, जो बाहरी झटकों के प्रति व्यापार संतुलन की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

सात तिमाहियों के बाद बढ़ा छोटी राशि के कर्ज का वितरण : आरबीआई

मुंबई/भाषा। सूक्ष्म कर्ज वितरण में लगातार सात तिमाहियों की गिरावट के बाद जनवरी-मार्च, 2026 तिमाही में पहली बार वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इस दौरान उधारकर्ताओं की संख्या में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंगलवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि हालिया तिमाही में कर्जदारों की संख्या में 22.7 लाख की कमी आई है। यह दर्शाता है कि भले ही ऋण देने की गतिविधियों में तेजी आने लगी है, लेकिन इस क्षेत्र के ग्राहक आधार में अब भी एकीकरण का दौर जारी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हो रहा है। 31 से 180 दिन तक बकाया रहने वाले ऋण का अनुपात लगातार पांचवीं तिमाही में घटा है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में लागू किए गए नियामकीय सुरक्षा उपायों के बाद ऋण गुणवत्ता में सुधार आया है। रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को ऋण देने वाले सभी प्रकार के कर्जदाताओं में बैंकों में 31 से 180 दिन तक बकाया रहने वाले ऋणों का अनुपात सबसे अधिक 2.5 प्रतिशत रहा। इसके बाद समग्र क्षेत्र और लघु वित्त बैंकों का यह अनुपात 2.0-2.0 प्रतिशत, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) का 1.9 प्रतिशत तथा अन्य एनबीएफसी का 1.6 प्रतिशत रहा। आरबीआई ने एक अन्य सकारात्मक रुझान का उल्लेख करते हुए कहा कि उधारकर्ताओं पर ऋण का बोझ कम हुआ है। मार्च, 2026 तक तीन या उससे अधिक संस्थानों से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी घटकर 9.7 प्रतिशत रह गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन को बल मिल रहा है।

अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मकता व निराशा फैला रहे हैं राहुल गांधी : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ''नकारात्मकता'' फैलाने तथा भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकने का आरोप लगाया और दावा किया कि आर्थिक ''सुनामी'' को लेकर राहुल गांधी की बार-बार की गई भविष्यवाणियां देश के आर्थिक प्रगति के सामने गलत साबित हुई हैं।

भाजपा की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार शाम सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में जनजीवन और कारोबार सुगमता में सुधार से जुड़े उपायों पर भी चर्चा हुई।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को ''नकारात्मकता का नवाब, निंदा करने का चैम्पियन और दुष्प्रचार करने वाला'' बताया। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, ''मोदी व भाजपा से नफरत करते-करते वह भारत से नफरत करने लगे हैं। वह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति के खिलाफ जहर उगलते हैं। हर अवसर पर वह कहते हैं कि भारत पर आर्थिक सुनामी आने वाली है।'' पूनावाला ने कहा, ''इसके उलट, भारत पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहा है। कोविड, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध जैसी तीन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारत 7.7-7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।'' उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज की सरकार ''रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म'' की सरकार है। उनका कहना था, ''जीएसटी सुधार से लेकर प्रत्यक्ष कर सुधार तक, ये सभी सुधार नागरिकों और कारोबार को केंद्र में रखकर किए गए हैं। यह नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण है।'' पूनावाला ने कहा, ''आज 'डी' का अर्थ विनियमन में कमी (डी-रेगुलेशन), विकेंद्रीकरण (डिसेंट्रलाइजेशन), विविधीकरण (डाइवर्सीफिकेशन), लोकतंत्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेशन) और डिजिटलीकरण है। सुधारों की इस यात्रा ने भारत को गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ाया है। देश लालफीताशाही से रेड कार्पेट की ओर बढ़ा है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर ''पांच प्रतिशत से अधिक नहीं'' रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अर्थव्यवस्था ने उन अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ''आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अनेक बाधाओं के बावजूद भारत ने मुद्रास्फीति को औसतन 4.5 से 5 प्रतिशत के आसपास बनाए रखा। आज हमारे पास सर्वाधिक निर्यात है।''

कांग्रेस राजनीति के अपराधीकरण का पर्याय बनती जा रही है : नितिन नवीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि देश को बांटने का प्रयास कर रही ताकतों का समर्थन करने के कारण यह राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के साथ-साथ राजनीति के अपराधीकरण का भी पर्याय बनता जा रहा है।

तेलंगाना के अपने तीन दिवसीय के दौरे के आखिरी दिन शहर के बाहरी इलाके में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि जनता और पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता ''राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर खर्च हुए सरकारी पैसे'' के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पर्याय हैं। मुझे लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण भी कांग्रेस का पर्याय बनता जा रहा है। जिस तरह से नापाक मंसूबों के साथ देश को बांटना चाह रही ताकतों को कांग्रेस का समर्थन मिलता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के लिए जानी जाएगी।''

भाजपा प्रमुख ने कहा कि राजग सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी (माल एवं सेवा कर) तथा आयकर में दी गई छूट से लोगों को राहत मिली है, जबकि तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ''आरआर कर'' के जरिए ''दिल्ली दरबार'' को पैसे भेजती है।

भाजपा ने ''आरआर कर'' शब्द का इस्तेमाल ''राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी कर'' के रूप में किया है।

नवीन ने कहा, ''मुझे हाल ही में पता चला है कि कांग्रेस ने अपनी परंपरा के अनुसार, (सरकार की) मूसी रिवरफ्रंट योजना में लूट-खसोट शुरू कर दी है। लेकिन, आपके माध्यम से हम कांग्रेस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता और तेलंगाना की जनता राहुल गांधी के विदेश दौरों पर खर्च किये जा रहे लोगों के खून-पसीने की कमाई का हिसाब आपसे जरूर मांगेंगे।''

अंबाला में चार वर्षीय लड़का खेलते समय 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा, बचाव अभियान जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अंबाला/भाषा। हरियाणा में अंबाला जिले के बराड़ा क्षेत्र के धनौरा गांव में मंगलवार को चार वर्षीय एक लड़का 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसे निकालने के कई एजेंसियों के समन्वय से प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़के पर नजर रखने के लिए लगभग नौ इंच चौड़े बोरवेल में एक कैमरा डाला गया है और बचावकर्मी रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ)और सेना के जवान बचाव अभियान के लिए मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि गत आठ घंटे से ज़्यादा समय से बचाव अभियान चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब धनौरा निवासी निर्भय अपने पिता के साथ खेत में अपने दादा के लिए खाना लेकर गया था। खेलते समय निर्भय का पैर फिसल गया और वह खुले बोरवेल में जा गिरा। सूचना मिलते ही उपायुक्त (डीसी) अजय सिंह तोमर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया है। जिला उपायुक्त तोमर ने बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई। उन्होंने बताया कि बोरवेल की चौड़ाई लगभग नौ इंच है। तोमर ने बताया कि एनडीआरएफ विशेष उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद है और मदद के लिए सेना से भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है।

हरियाणा, असम और पंजाब नये आपराधिक कानूनों को लागू करने में सबसे आगे

नई दिल्ली/भाषा। दो साल पहले लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के मामले में हरियाणा, गोवा, असम, चंडीगढ़ और पंजाब देश के पांच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि हर राज्य के प्रदर्शन का आकलन चार पैमानों -प्रशासनिक सुधार, कामकाज की दक्षता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का इस्तेमाल और एकीकरण- पर मिले अंकों के आधार पर किया जाता है। इन पैमानों का महत्व अलग-अलग होता है और इनमें समय-समय पर बदलाव और संशोधन किए जाते हैं। तीन नये आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023- ने ब्रिटिश-युग के आपराधिक कानूनों की जगह ली थी और इन्हें एक जुलाई, 2024 को लागू किया गया था। यह देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक अहम मोड़ था। अधिकारियों ने बताया कि नये कानूनों का मकसद प्राथमिकी से लेकर उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले तक की प्रक्रिया को तीन साल के अंदर पूरा करना है। इन कानूनों में एक सामान्य मंच, 'अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली' (आईसीजेएस) की परिकल्पना की गई है।

वरिष्ठ पत्रकार का पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं करना प्रतिशोध की राजनीति : वेणुगोपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार आर. राजगोपाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद उनका पासपोर्ट नवीनीकरण रोका गया तथा सरकार एक ''सच्चे पत्रकार'' को निशाना बना रही है।

वेणुगोपाल ने इसे ''प्रतिशोध की राजनीति'' करार देते हुए कहा कि सरकार ऐसे पत्रकार को निशाना बना रही है, जो बिना किसी डर के लिखते हैं। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''यह पूरी तरह प्रतिशोध की राजनीति है और उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक सच्चे पत्रकार हैं, जो बिना भय के लिखते हैं। वे (सरकार) एक खतरनाक परंपरा स्थापित कर रहे हैं, जिसमें पहले एसआईआर के जरिए आपको मतदाता सूची से बाहर किया जाता है और फिर एक-एक करके महत्वपूर्ण दस्तावेजों से वंचित कर आपकी नागरिकता छीनने की कोशिश की जाती है।'' वेणुगोपाल ने दावा किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के साथ भी इसी तरह का अन्याय हो रहा है क्योंकि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राशन लाभ से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''राजगोपाल एक ईमानदार भारतीय नागरिक हैं और उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करना भारत के संविधान के खिलाफ है।''

परिवारों पर कर्ज सितंबर, 2025 में जीडीपी के 45.5 प्रतिशत तक पहुंचा : रिपोर्ट

मुंबई/भाषा। गैर आवासीय खुदरा ऋण में बढ़ोतरी के कारण परिवारों पर कुल कर्ज देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 45.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में यह खुलासा हुआ है। आरबीआई ने कहा कि परिवारों पर कर्ज में बढ़ोतरी की वजह गैर-आवासीय खुदरा ऋण में हुई वृद्धि थी, जो मार्च, 2026 तक कुल कर्ज का 58.4 प्रतिशत था। समय के साथ इन ऋणों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। इसने आवास, कृषि तथा कारोबारी ऋणों की तुलना में तेज गति प्राप्त की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, परिवारों पर कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद, उधार लेने वालों की 'प्रोफ़ाइल' में सुधार जारी है। बकाया राशि और उधार लेने वालों की संख्या, दोनों ही मामलों में बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं (प्राइम और उससे ऊपर) की हिस्सेदारी बढ़ी है।

रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर, 2023 से देश में परिवारों पर कर्ज का जीडीपी में हिस्सा उसके पांच वर्ष के औसत 42.9% से ऊपर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञ लगातार परिवारों पर कर्ज में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनका मानना है कि परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा ऐसे ऋणों की किस्त चुकाने में खर्च हो रहा है, जिनसे खरीदी गई परिसंपत्तियों, जैसे वाहन का मूल्य समय के साथ घटता जाता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू कर्ज के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। थाइलैंड में परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 87.3%, मलेशिया में 69.9% और चीन में 59% है।

अमरनाथ यात्राः सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, करीब 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ाने और लगभग 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था समेत कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का पहला जत्था दो जुलाई को यहां भगवती नगर स्थित आधार शिविर से रवाना होगा। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अध्यक्ष) सुबह चार बजे पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे।

अमरनाथ गुफा मंदिर 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 57 दिन की अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई को शुरू होगी। यह यात्रा अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में छोटे लेकिन अधिक चढ़ाई वाले 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू होगी। जम्मू संभाग के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ''अभी तक जम्मू संभाग में लगभग 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जम्मू संभाग में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने, भोजन और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो।'' जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती के साथ मौजूद कुमार ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाज किए गए हैं। तूती ने कहा, ''श्री अमरनाथ जी यात्रा हर साल होने वाला आयोजन है। हर साल इस यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और इस साल हम पहले से भी अधिक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि सुबह छह बजे से आठ बजे के बीच लखनपुर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षा घेरे में जम्मू ले जाया जाएगा, जबकि आठ बजे के बाद आने वालों को सुरक्षा कारणों से वहीं रुकना होगा। उन्होंने कहा, ''तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही यात्रा करने का निर्देश दिया गया है।''

गुजरात बड़े रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है : राजनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वडोदरा/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है तथा अपनी औद्योगिक ताकत, दक्ष श्रमिकों और उद्यमिता की भावना के जरिए भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में अहम भूमिका निभा सकता है।

यहां मध्य गुजरात क्षेत्र के लिए चौथी 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' (वीजीआरसी) के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में रक्षा उत्पादन और निर्यात में काफी प्रगति की है, लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ''अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है।'' उन्होंने कहा कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 के लगभग 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसी दौरान रक्षा निर्यात लगभग 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए हो गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा, ''हालांकि, मैं इसे सिर्फ शुरुआत मानता हूं। हमें अभी लंबा सफर तय करना है और मेरा मानना है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में गुजरात बहुत अहम भूमिका

निभा सकता है।'' रक्षा विनिर्माण में गुजरात के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि वडोदरा टाटा-एयरबस सी-295 ट्रांसपोर्ट विमान कार्यक्रम के तहत भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैन्य विमान विनिर्माण केंद्र है, और इसे देश की एयरोस्पेस यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के सबसे अत्याधुनिक तोपखाना प्रणालियों में से एक, के9 वज्र प्लेटफॉर्म का निर्माण गुजरात में किया जाता है, जिससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी बढ़ गई है। सिंह ने कहा कि साणंद और धोलेरा में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर केंद्र भारत की प्रौद्योगिकीय संप्रभुता की नींव बनेंगे, जबकि रसायन, पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, बंदरगाह, जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्रों में गुजरात की ताकत अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में मदद कर सकती है।

मंत्री ने कहा कि रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग पर आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान उन्होंने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्टार्टअप के प्रतिनिधियों से बातचीत की तथा भारत में रक्षा विनिर्माण बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए। सिंह ने गुजरात को भारतीय अर्थव्यवस्था का ''विकास इंजन'' बताते हुए कहा कि 2003 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई 'वाइब्रेंट गुजरात' पहल अब एक वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले मंच के रूप में विकसित हो चुकी है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि के अनुरूप है।

एसआईआर के तहत घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने का अभियान शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत घर-घर जाकर गणना का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी चुनावों के लिए स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है कि अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल न हों। इस बीच, राज्य सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और पूरे राज्य में डिजिटल तथा विकेंद्रीकृत सेवा माध्यमों के जरिए समयबद्ध तरीके से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए एक परिचालन रूपरेखा अधिसूचित की है।

राजस्व विभाग ने कहा कि इस नए ढांचे का उद्देश्य स्थायी निवास प्रमाणित करने के लिए एक समान, पारदर्शी और कानूनी रूप से टिकाऊ व्यवस्था स्थापित करना है। साथ ही इसे कर्नाटक सकल सेवा अधिनियम, 2011 तथा मौजूदा डिजिटल प्रशासनिक मंच से जोड़ा जाएगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) कर्नाटक राज्य में स्थायी निवास का प्रमाण माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जहां भी लागू कानूनों, सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं या योजनाओं के दिशा-निर्देशों में स्थायी निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी, वहां इसके लिए एक समान व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी जांच और सत्यापन के बाद यदि संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक वास्तव में कर्नाटक का स्थायी निवासी है, तो उसे पीआरसी जारी किया जा सकता है।

आदेश में पात्रता तय करने के लिए कई आधार बताए गए हैं। इनमें कर्नाटक में जन्म, राज्य में कम से कम 10 वर्ष का सामान्य निवास, कक्षा 12 या समकक्ष तक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मंगलवार को बेंगलूरु के सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर परिवार के सदस्यों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर की जा रही गणना प्रक्रिया में भाग लेते हुए।

कर्नाटक के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कम से कम 10 शैक्षणिक वर्षों तक अध्ययन, माता-पिता या जीवनसाथी का राज्य में निवास, आवासीय संपत्ति का स्वामित्व या वैध कब्जा, मतदाता सूची, आधार या राशन कार्ड जैसे सरकारी अभिलेखों में नाम, कर्नाटक में कम से कम सात वर्ष तक सरकारी या सार्वजनिक सेवा, पात्र निवासी से विवाह तथा अन्य विश्वसनीय दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक साक्ष्य शामिल हैं, जो यह साबित करें कि कर्नाटक ही आवेदक का मुख्य और स्थायी निवास है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये आधार केवल उदाहरण हैं, अंतिम नहीं। इनमें से किसी एक शर्त का पूरा न होना किसी आवेदक को स्वतः अपात्र नहीं बनाएगा। आदेश में कहा गया है कि प्रमाणपत्र जारी करने या अस्वीकार करने का प्रत्येक निर्णय कारण सहित लिखित आदेश के रूप में होना चाहिए।

आदेश के अनुसार, उप तहसीलदार, तहसीलदार या अन्य अधिकृत अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे। प्रमाणपत्र से संबंधित आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर सहायक आयुक्त के समक्ष अपील तथा 60 दिनों के भीतर उपायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुकुमार ने सोमवार को बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 30 जून से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही 2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। मसौदा मतदाता सूची पांच अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त से चार सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। जहां आवश्यक होगा, वहां नोटिस जारी किए जाएंगे और पांच अगस्त से तीन अक्टूबर के बीच दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अंबुकुमार ने कहा, कर्नाटक में इस अभियान के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार है। हमने 68,123 अधिकारियों को तैनात किया है, जिनमें 59,050 बूथ स्तरीय अधिकारी, 7,556 बूथ स्तरीय पर्यवेक्षक और 224 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वे इस कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों ने लगभग 1.15 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं, जिनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कर्नाटक के मतदाताओं से एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को राज्य के मतदाताओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने, 29 जुलाई की निर्धारित समय-सीमा से पहले गणना प्रपत्र जमा करने और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की, ताकि उनके मतदाता रिकॉर्ड अद्यतन बने रहें। अपना गणना प्रपत्र जमा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में शिवकुमार ने कहा कि एसआईआर अभियान मंगलवार से पूरे राज्य में शुरू हो गया है। इसके तहत बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को सलाह दी कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी माध्यम का उपयोग करें। उन्होंने कहा, ''हम सभी को अपने मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए।''

मुख्यमंत्री ने लोगों से निर्धारित समय के भीतर भरे हुए गणना प्रपत्र वापस जमा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया उनके अपने आवास से भी शुरू हो चुकी है और उन्होंने अपना गणना प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, वे अपने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग कर ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, वे चुनाव अधिकारियों की मदद से उसे अपडेट करा सकते हैं।

शिवकुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और पर्यवेक्षकों ने मतदाताओं की सहायता के लिए पहले ही व्हाट्सऐप समूह बना लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर हों, तो परिवार का कोई भी जिम्मेदार वयस्क सदस्य पूरे परिवार की ओर से गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मतदाता अपनी पुरानी तस्वीर बदलना चाहता है, तो वह नयी तस्वीर जमा कर सकता है। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार का विवरण केवल पहचान के उद्देश्य से दर्ज किया जा सकता है।

मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ने की संभावना पर शिवकुमार ने कहा कि कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसे लोगों को सरकारी लाभ देना बंद कर दिया है, जो मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में इसी तरह के मानदंड अन्य राज्यों में भी अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ''यदि कोई व्यक्ति अब यहां का मतदाता नहीं है, तो हम उसे गारंटी योजनाओं का लाभ क्यों देते रहें? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान का मतदाता है, लेकिन यहां सरकारी गारंटी योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।''

'कारा हुन्निमे उत्सव' के दौरान झड़प में आठ लोग घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हावेरी। कर्नाटक के हावेरी में कारा हुन्निमे उत्सव के तहत आयोजित बैल जुलूस के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर हुई झड़प में आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को हंगल तालुक के नरेगल गांव में हुई। अधिकारियों ने बताया कि झड़प के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कारा हुन्निमे मुख्य रूप से उत्तरी कर्नाटक में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पारंपरिक कृषि उत्सव है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घटना की शुरुआत दो व्यक्तियों के बीच झगड़े से हुई थी जो बाद में झड़प में बदल गई। उन्होंने इस घटना में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कारा हुन्निमे उत्सव के लिए बैलों का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी एक मस्जिद के पास पटाखे फोड़े गए, जिसे लेकर दो व्यक्तियों के बीच बहस हो गई थी। इसमें कथित तौर पर धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे आठ लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, कर्नाटक के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू त्योहारों और परंपराओं को बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। भाजपा नेता ने गृह मंत्री प्रियंक खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देखना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य को कहां लाकर खड़ा कर दिया है।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि परंपरा के अनुसार, किसान कारा हुन्निमे के दौरान अपने सजाए गए बैलों का जुलूस निकालते समय पटाखे फोड़ते हैं।

अशोक ने कहा, ऐसा आरोप है कि सिर्फ इसी वजह से धार्मिक चरमपंथियों ने किसानों पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से घटना में शामिल सभी लोगों की तुरंत गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से घायल किसानों का इलाज का खर्च उठाने का भी आग्रह किया।

निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हमारे सवालों का जवाब दे : प्रियंक खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने मंगलवार को एक बार फिर निर्वाचन आयोग से मांग की कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे। इस बीच, मंगलवार को कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और स्वयं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपना गणना प्रपत्र भरा। खरगे ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोग इस मुद्दे पर अपनी उलझनें दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय नहीं जा सकते। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि कांग्रेस कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि मतदाता सूची त्रुटिरहित और सटीक तरीके से तैयार की जाए तथा यह कार्य निर्वाचन आयोग ही कर सकता है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियंक ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हमारा कहना है कि जो भी योग्य हैं, उन सभी को शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और केरल में नागरिकों के बीच काफी भ्रम पैदा हो गया है। क्या यह कहना गलत है कि यहां ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए?'' मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से 12 सवाल पूछे थे, लेकिन आयोग ने उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग बताए कि हमारे 12 सवालों में से कौन-सा सवाल बेतुका, असंवैधानिक या गैर-कानूनी है। हम तैयार हैं। क्या केवल उसे ही कानून की जानकारी है? क्या केवल वह ही संविधान का ज्ञाता है? अगर हमें कोई शक है, तो क्या हमें निर्वाचन आयोग से नहीं पूछना

चाहिए? हमें क्या करना चाहिए-क्या हम अपने पत्र भाजपा कार्यालय में जमा करें? हमने उस प्राधिकार से संपर्क किया है जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब जवाब देना उसी का काम है।''

प्रियंक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ''अगर आप निर्वाचन आयोग से कोई सवाल पूछते हैं, तो भाजपा जवाब देती है। अगर आप आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)से कोई सवाल पूछते हैं, तो भाजपा जवाब देती है। अपनी पार्टी से जुड़े मामलों को छोड़कर, वह बाकी हर चीज़ का जवाब देती है। क्या यह अजीब नहीं है?'' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने निर्वाचन आयोग को अपनी 'कठपुतली' बना लिया है। मंत्री ने आरोप लगाया, ''केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग को अपना कठपुतली बनाने की कोशिश की है। असल में, वे ऐसा कर भी चुके हैं।'' उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई), मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली समिति का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें हटाकर उनके स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। इसका अभिप्राय है कि चाहे किसी को भी चुना जाए, तीन सदस्यों वाली इस समिति को असल में प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा।

प्रियंक ने कहा कि 80 सांसदों को निलंबित करने के बाद,भाजपा ने एक कानून के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त को न्यायिक समीक्षा से छूट दी, जिसका अभिप्राय है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह जो कुछ भी करते हैं, उस पर किसी भी कानून के तहत या किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा से छूट मिलने के बाद, निर्वाचन आयोग ने एसआईआर शुरू की। प्रियंक ने कहा, ''उन्होंने केरल, बिहार और तमिलनाडु में प्रयोग (एसआईआर) किए, जिनमें कई कमियां सामने आईं। पश्चिम बंगाल में, उन्होंने तार्किक विसंगति का विचार पेश किया। तार्किक विसंगति के बहाने, कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया।'' उन्होंने कहा कि एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसके प्रमुख उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। न्यायाधिकरण के सामने लगभग 27 लाख याचिकाएं दायर की गईं। बाद में उक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि काम पूरा नहीं हो सकता और इसमें चार साल लगेंगे। प्रियंक ने कहा, ''इसके बाद अदालत ने कहा कि वे लोग इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे और इस मामले पर अगली बार विचार किया जाएगा।

इस घटनाक्रम को समझिए। यह सब क्यों किया जा रहा है? आपके अधिकार छीनने के लिए।'' मंत्री ने आरोप लगाया कि असम में परिसीमन किया गया और जनसांख्यिकीय संतुलन बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी और अब वे परिसीमन आयोग पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। प्रियंक ने आरोप लगाया, ''आज वे दो-तिहाई बहुमत के लिए इतने बेताब क्यों हैं? वे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दो-तिहाई बहुमत मिलने पर वे एक बार फिर वह विधेयक पेश कर सकते हैं और परिसीमन आयोग पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन हथकंडों के खिलाफ लड़ रही है।

स्वागत

मंगलवार शाम को बेंगलूरु एचएएल एयरपोर्ट पर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे।

उद्घाटन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मंगलवार को बेंगलूरु के कंटीरवा स्टेडियम में कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा आयोजित 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026' कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों के साथ।

एनएमआईटी में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों का हुआ ओरिएंटेशन

बेंगलूरु। निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमआईटी), बेंगलूरु में शैक्षणिक वर्ष 2026-30 बैच के बीटेक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 1,400 नवप्रवेशित छात्रों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि किशोर पी. दुर्ग, वरिष्ठ प्रबंध निदेशक एवं ग्लोबल लीड, एक्सेंचर लर्नवेंटेज एंड मिड मार्केट ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी परिवर्तन अब अभूतपूर्व गति से हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नई तकनीकें समाज को तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बदलते दौर के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए अपने कौशल और ज्ञान के माध्यम से मूल्य सृजित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों से चुनौतियों और अवसरों को समान रूप से स्वीकार कर भविष्य के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दूसरे दिन कर्नाटक हाइब्रिड माइक्रो डिवाइसेस लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलूरु के पूर्व प्रोफेसर डॉ. ई. द्वारकादास ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सफलता केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा निर्माण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि और जुनून के अनुरूप मार्ग चुनकर उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में एनएमआईटी के प्राचार्य डॉ. एच.सी. नागराज ने नवप्रवेशित छात्रों का स्वागत किया तथा अनुशासन और समय प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उप-प्राचार्य डॉ. जे. सुधीर रेड्डी ने संस्थान की उद्योग समर्थित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग तथा विभिन्न शैक्षणिक पहलों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता निट्टे एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित पुंजा ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को कॉलेज जीवन में मजबूत मित्रता और सहयोगी नेटवर्क विकसित करने की सलाह देते हुए कहा कि छात्र जीवन में बने संबंध भविष्य में भी महत्वपूर्ण सहारा बनते हैं। इस अवसर पर निट्टे (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) बेंगलूरु परिसर की उप-पंजीयक डॉ. कविता कामथ, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रत्यायन निदेशक डॉ. किरण ऐथल, परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रशांत वी., प्रथम वर्ष बीटेक समन्वयक डॉ. सुमाश्री एस. सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. हीता डी. शेट्टी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

आर. अशोक ने बेंगलूरु के लिए धन आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री शिवकुमार पर साधा निशाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से सवाल किया कि क्या वह केवल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों के ही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बेंगलूरु के बुनियादी ढांचे और सड़क विकास के लिए घोषित 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज के 'भेदभावपूर्ण आवंटन' का आरोप भी लगाया। अशोक ने यह भी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले बेंगलूरु के लाखों निवासी कर नहीं चुकाते हैं।

आर. अशोक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, क्या आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं या केवल कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों के? उन्होंने आरोप लगाया, बेंगलूरु के बुनियादी ढांचे और सड़क विकास के लिए घोषित 2,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों के साथ बेहद भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। अशोक ने दावा किया, एक ओर कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। वहीं दूसरी ओर, राजधानी के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले 16 निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है और उन्हें केवल प्रतीकात्मक राशि दी गई है, मानो उन्हें दान दिया जा रहा हो। खबरों के अनुसार, आवंटन सूची से पता चलता है कि कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों जैसे चामराजपेट, गांधी नगर, विजयनगर, शांतिनगर, हेब्बल, गोविंदराज नगर, पुलकेशी नगर, शिवाजीनगर, बीटीएम लेआउट, सर्वज्ञनगर और ब्यातरायनपुरा को 100-100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटन 40 करोड़ रुपये से 80 करोड़ रुपये के बीच है।

अभयसूर्या ने जीतो चार गोल्ड मेडल

बेंगलूरु। सेंट जोसेफ स्कूल के क्लास दसवीं के विद्यार्थी पी. अभयसूर्या ने बेंगलूरु में हुई कर्नाटक स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में चार गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने यह कामयाबी 10-मीटर ओपन एयर साइट राइफल इवेंट कैटेगरी में हासिल की। अभय ने मेन्स, मेन्स जूनियर, यूथ और मेन्स सब-यूथ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या और शहरी विकास मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्दरामय्या ने मंगलवार को मेडल जीतने वाले अभय सूर्या को बधाई दी और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। अभय सूर्या पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के मीडिया एडवाइजर केवी प्रभाकर और मीरा के बेटे हैं।

यमुना जल समझौते के बाद जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंगलवार को जयपुर हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एक दिन पहले ही राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे राज्य के जल संकटग्रस्त शेखावाटी क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मंगलवार को नयी दिल्ली से लौटे, जहां वर्ष 1994 के अपर यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) समझौते के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

हवाई अड्डे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र से आए लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। टर्मिनल भवन से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के बाहर बनाए गए विशेष मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनका माल्यार्पण किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ई-बस से भाजपा प्रदेश मुख्यालय के लिए रवाना हुए। रास्ते में गांधी सर्किल और रामबाग सर्किल पर भी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए यमुना का पानी लेकर आए हैं और इस पर केवल शेखावाटी ही नहीं, बल्कि पूरा राजस्थान गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूरे राज्य को लाभ होगा। यमुना नदी का पानी उपलब्ध होने से वर्तमान पेयजल स्रोतों पर दबाव कम होगा और एक क्षेत्र को मिलने वाला पानी अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को इस दिन को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा, जब राजस्थान में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार की गयी। सभी की मांग थी कि यदि राजस्थान को पर्याप्त पानी मिलेगा तो राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे किसानों को सिंचाई के लिए, उद्योगों को उत्पादन के लिए और आम जनता को पेयजल के लिए पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, बीसलपुर परियोजना, ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर तक पानी लाने की योजना तथा नर्मदा परियोजना सहित कई योजनाएं 40 से 50 वर्षों से लंबित थीं, जिन पर उनकी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का विकास पेयजल, कृषि और उद्योग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है और उनकी सरकार ने वर्षों से लंबित इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पांच दिन पहले कांग्रेस के नेता कुछ और कह रहे थे। अब समझौता होने के बाद उनके सुर बदल गए हैं।

शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शेखावाटी क्षेत्र के साथ अन्याय किया। उनके अनुसार, चुनाव के समय केवल शिलान्यास किए गए और लोगों को यमुना का पानी मिलने के सपने दिखाए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जब राजस्थान, हरियाणा और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने का गंभीर रूप से प्रयास नहीं किया गया और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र तक नहीं लिखा गया। भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के कार्यकाल में 3,900 मेगावाट बिजली उत्पादन किया था, जबकि उनकी सरकार ने सवा दो वर्ष में 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की दिशा में काम किया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था, लेकिन कई क्षेत्रों में इसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है और पिछले तीन महीनों के दौरान जब बिजली की मांग सबसे अधिक रहती है, तब भी राज्य अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, वे कहते हैं कि आलू से सोना बनाएंगे। यह हम नहीं कर सकते, लेकिन हम यमुना का पानी लेकर आएंगे, जिससे हमारा किसान जरूर सोना पैदा करेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से शेखावाटी के लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है।

सोमवार को नयी दिल्ली में हुए एमओयू के बाद पहले चरण में सूखाग्रस्त चूरू, झुंझुनूं और सीकर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्ष 1994 में यमुना बेसिन राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत राजस्थान को मानसून के दौरान 1,917 क्यूसेक यमुना जल आवंटित किया गया था। हालांकि, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य दशकों तक अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर सका।

परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी चूरू में प्रस्तावित जलाशय तक लाया जाएगा। वहां से इसे लाभार्थी क्षेत्रों में पेयजल के रूप में वितरित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से भूजल पर निर्भरता कम होगी, पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा और जल संकट से जूझ रहे शेखावाटी क्षेत्र के 75 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

न्यायालय ने आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली/जयपुर। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2013 के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम द्वारा दायर उस याचिका पर राजस्थान सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने जेल अधिकारियों को आसाराम को मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दिया और कहा कि जमानत देने पर तभी विचार किया जाएगा, जब उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद ही इस बात पर विचार करेंगे कि क्या जमानत देने की कोई गंभीर आवश्यकता है, जैसे कि ऐसी स्थिति जिसमें उसके जीवन को खतरा हो।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने कहा कि आसाराम की उम्र 80 साल से ज्यादा हो गयी है और वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 मई को इस मामले में आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता (भादंसं) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चे के सामूहिक दुष्कर्म और प्रवेशन (पेनिट्रेटिव) यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने आसाराम को भादंसं की धारा 376(डी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)/6 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने उसे आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धारा 120(बी) के आरोप से भी दोषमुक्त कर दिया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय की पीठ ने भादंसं की धारा 376(2)(एफ) के तहत आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जो नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित है। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा भी बरकरार रखी गयी। उच्च न्यायालय ने इसके अलावा भादंसं की कई अन्य धाराओं के तहत भी उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इनमें धारा 342 (गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाना), धारा 370(4) (मानव तस्करी), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (महिला का शील भंग करना) और धारा 354(ए) (यौन उत्पीड़न) शामिल हैं। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के तहत भी उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

पीठ ने इसके अतिरिक्त भादंसं की धारा 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 के तहत भी आसाराम की दोषसिद्धि को कायम रखा। उच्च न्यायालय ने इस मामले के सह-आरोपी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी और शरत चंद्र को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि, सभी विद्यालय भवनों की गहन जांच सुनिश्चित करें : यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा, मरम्मत कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में जर्जर अथवा असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए।

बैठक में एसीएस यादव ने निर्देश दिए कि पूर्व में चिन्हित जर्जर विद्यालय भवनों के साथ-साथ वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे सभी विद्यालय भवनों की पुनः गहनता से जांच कराई जाए। प्रत्येक भवन की सुरक्षा का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा सुरक्षा संबंधी सभी मानकों और नियमों की पूर्ण पालना की जाए। उन्होंने कहा कि जो भवन या कक्ष किसी भी दृष्टि से असुरक्षित पाए जाएं, उन्हें तत्काल प्रभाव से लॉक किया जाए, बैरिकेडिंग कर उपयोग से बाहर किया जाए तथा उनकी यथास्थिति की विस्तृत रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जाए।

यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्यों एवं नवीन भवनों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में शिक्षा विभाग की विभिन्न प्रमुख योजनाओं, गतिविधियों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा, जिससे योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से विद्यार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राज्यभर में 2,000 से अधिक विद्यालयों से संबंधित विकास एवं निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2026-27 में लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के विकास के लिए भामाशाहों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) तथा अन्य उपलब्ध मदों से भी सहयोग एवं वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, ताकि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में आवश्यक विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य प्रभावी ढंग से कराए जा सकें।

बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मी शर्मा, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट, संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार खिंची, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-खख अशोक कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता गिरिराज गुप्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

फलोदी में दंपति और दो बच्चों के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर। राजस्थान के फलोदी जिले के देचू क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को एक मकान से दंपति और उनके दो बच्चों के शव बरामद किए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गेनाराम (35), उसकी पत्नी पुष्पा (32), बेटी खुशबू (13) और बेटे किशन (10) के रूप में हुई है।

फलोदी के पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया, गेनाराम का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव चारपाई पर पड़े थे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुलाया गया है। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद स्वयं फंदा लगा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।

राजस्थान के बाघ अभयारण्य के नीचे बनी देश की पहली आठ-लेन की सुरंग अगस्त में खुलेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। बुनियादी ढांचा विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के कोटा जिले में एक बाघ अभयारण्य के नीचे बनी भारत की पहली आठ-लेन वाली राजमार्ग सुरंग इस साल अगस्त में सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर खुलने जा रही है। वर्तमान में इस सुरंग में हल्के वाहनों के साथ सुरक्षा परीक्षण किये जा रहे हैं। सुरक्षा निरीक्षणों के पूरा होने के बाद दिल्ली-वडोदरा खंड पर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (एमएचटीआर) के नीचे स्थित 4.9 किलोमीटर लंबी इस 'ट्विन-ट्यूब' (दोहरी) सुरंग को शुरुआत में कारों और आपातकालीन वाहनों के लिए खोला गया है।

अधिकारियों द्वारा सुरंग के भीतर सुरक्षा प्रणालियों और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े अतिरिक्त आकलन पूरे किए जाने के बाद ही भारी वाहनों और अन्य सभी यातायात को इसमें से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), कोटा के परियोजना निदेशक संदीप अग्रवाल ने 'पीटीआई-भाषा' से फोन पर बातचीत में कहा, एमएचटीआर के नीचे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनी इस आठ-लेन राजमार्ग सुरंग को अब सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं खोला गया है। फिलहाल, कार जैसे हल्के वाहनों के साथ केवल परीक्षण किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सुरंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि सुरंग के भीतर अन्य काम नियमित परीक्षण के साथ-साथ किए जा रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के बाद आगामी अगस्त में इस सुरंग को सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर खोले जाने की संभावना है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा न डालने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए इस सुरंग का निर्माण पूरी तरह से बाघ अभयारण्य के नीचे किया गया है।

इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि जानवर राजमार्ग के यातायात से प्रभावित हुए बिना सुरंग के ऊपर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ परिवहन बुनियादी ढांचे के एकीकरण का एक अनुकरणीय उदाहरण है।

इस सुरंग में दोहरी ट्यूब हैं, जिनमें से प्रत्येक में चार लेन का मार्ग है। इसके साथ ही यह किसी वन्यजीव अभयारण्य के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली आठ लेन की सुरंग बन गई है। सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए इसके निर्माण में विशेष अभियांत्रिकी तकनीकों का उपयोग किया गया है।

विरोध

बीकानेर में मंगलवार को पीबीएम सरकारी अस्पताल में कथित कुप्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता और समर्थक। इस प्रदर्शन में कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, जिसके दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी।

उच्च न्यायालय ने चुनाव संबंधी याचिका की खारिज, विधायक बनावत पर एक लाख का जुर्माना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बयाना से चुनी गईं निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि विधायक ने अपनी संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ हो या जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता हो। हालांकि, न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ ने चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान लंबे समय तक समन से बचने के कारण ऋतु बनावत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि उनके इस आचरण से न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से करीब 10 महीने की देरी हुई। अदालत ने सोमवार को विधायक ऋतु बनावत को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर यह राशि याचिकाकर्ता को अदा करें। यह चुनाव याचिका बयाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके पुरुषोत्तम लाल ने दायर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋतु बनावत ने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए फॉर्म-26 में अपनी संपत्तियों, देनदारियों, बैंक खातों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि शपथपत्र के कई कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे और कुछ जानकारियां जानबूझकर छिपाई गई थीं, जिससे मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि प्रत्याशी के रूप में बनावत द्वारा कथित रूप से कोई जानकारी छिपाने या उसका खुलासा नहीं करने से चुनाव परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा या यह चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

जयपुर में कल से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, भजनलाल करेंगे उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत 2047 : एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस' रखा गया है। दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में नीति-निर्माता, सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होंगे, जो डिजिटल गवर्नेंस और जनसेवा वितरण को सशक्त बनाने में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 10 स्वर्ण, छह रजत और एक जूरी पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार केंद्र एवं राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, ग्राम पंचायतों तथा शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्ट पहल के लिए प्रदान किए जाएंगे।

बच्चों को लेकर जा रही निजी विद्यालय की वैन में लगी आग

जयपुर। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मंगलवार को कंचनिया की ढाणी के पास करीब दस बच्चों को लेकर जा रही एक निजी विद्यालय की वैन में अचानक आग लग गई, हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब वैन कॉपर क्षेत्र से बच्चों को लेकर सिंघाना की ओर जा रही थी। यह वाहन सिंघाना के एक निजी प्ले स्कूल का था।

चालक ने वैन से धुआं और आग की लपटें निकलती देख तुरंत उसे रोक दिया। आग पूरे वाहन में फैलने से पहले ही चालक ने फुर्ती दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

श्रद्धांजलि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदानों को याद किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह की याद में हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह का नेतृत्व झारखंड में सिदो और कान्हू मुर्मू भाइयों ने किया था। राज्यपाल गंगवार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने रांची के मोरहाबादी मैदान में सिदो और कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज आस्था की वकालत कर रहे : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रामपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि राम भक्तों पर ''गोली और लाठी'' चलाने वाले तथा भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले ही आज आस्था की वकालत करते नजर आ रहे हैं।

आदित्यनाथ ने रामपुर में 690 करोड़ रुपए की लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रही है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 से पहले 'जय श्रीराम' बोलने पर लाठियां बरसाई जाती थीं। जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहते थे कि 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे', तब उन्हीं राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थीं। आज वही लोग आस्था की वकालत करते दिखाई दे रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय जनता को देते हुए कहा, ''यह आपकी ताकत है कि उन्हें आपके पीछे-पीछे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह आपके वोट की ताकत है। अब उन्हें पाप और कर्मों पर पश्चाताप होता होगा। अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि सपा गलत थी।'' उन्होंने कहा, ''जो कांग्रेस 2017 से पहले भगवान श्रीराम और भगवान

श्रीकृष्ण के अस्तित्व को नकार चुकी थी, आज वही कह रही है कि राम तो सबके हैं। अब सभी अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन प्रभु श्रीराम जगत के नियंता हैं। वे भी जानते हैं कि सही कौन है और गलत कौन।'' आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों की तुलना 'कालनेमी' के छल-कपट से करते हुए कहा कि जनता इनके झूठ व दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस व सपा का शासनकाल अन्याय व अराजकता का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, ''2017 से पहले का रामपुर और उसके बाद का रामपुर आपके सामने है। एक समय यहां गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे। वाल्मीकि समाज को उनकी जमीनों से वंचित कर दिया जाता था।'' उन्होंने कहा, ''जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, तो वह अन्याय का पर्याय बन जाती है। सपा की सरकार में यहां दलितों और गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने दबाने का काम किया था।'' योगी ने प्रदेश में भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ''रामपुर से निकला संदेश पूरे प्रदेश में गया। सपा की निरंकुश सत्ता को बदलने का परिणाम है कि आज रामपुर की नई पहचान बनी है और वह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा, ''जो विकास योजनाएं पहले असंभव लगती थीं, वे आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हुई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और यही विश्वास विकास की सबसे बड़ी आधारशिला बना।''

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में अचानक बाढ़, भूस्खलन से भारी तबाही

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 14 गांवों में अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन से 3,100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) ऑगस्टी जामोह ने बताया कि इस आपदा से नारी-कोयू विधानसभा क्षेत्र में धान के खेतों, निजी संपत्ति और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। तबिरीपो साकू, लोग्लू, रोटे, रामे और कोयू समेत कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है जिससे लगभग 500 परिवार अलग-थलग पड़ गए हैं। हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

जामोह ने बताया कि जिला प्रशासन ने सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राज्य पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने

राहत अभियान शुरू किया और वे सड़क संपर्क बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कुरंग कुमे के डीआईपीआरओ डेविड कोयू ने बताया कि इलाके का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया जिससे धान के खेतों, बागानों और कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है जो कि स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन हैं। कोयू प्रभावित रोटे गांव के निवासी हैं। बाढ़ में कई वाहन बह गए और बड़ी संख्या में सूअर और मुर्गियों समेत कई पशु भी मारे गए। आपदा के कारण ग्रामीणों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेना पड़ा जहां कई लोग फंसे हुए हैं। इस बीच दो मकान जलकर नष्ट हो गए, हालांकि उन मकानों के निवासी वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि रोटे गांव का झूला पुल बह गया और वहां तक जाने वाली सड़कें और पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया। गांव की जलापूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है जबकि बिजली के खंभे और बिजली की लाइनें बाढ़ के पानी में बह गईं।

राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, जांच जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उस समय हुआ है, जब कुछ दिन पहले चंपत राय ने इस विवाद की 'नैतिक जिम्मेदारी' लेते हुए पद छोड़ने की पेशकश की थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से पुष्टि की कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनसे कब, कहां और कितनी देर तक पूछताछ की गई। अधिकारी ने कहा, ''हां, उनका बयान दर्ज किया गया है।'' पुलिस अधिकारी ने हालांकि इससे अधिक जानकारी

देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे अयोध्या के क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष तिवारी ने कारसेवकपुरम स्थित चंपत राय के 'भारत कुटी' आवास पर जाकर उनका बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने चंपत राय से चढ़ावे के कथित गबन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज मांगे। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक विवाद बनने से पहले ही उन्हें इस कथित गड़बड़ी की जानकारी हो गई थी। मीडिया में आई उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर, जिनमें दावा किया गया था कि चंपत राय ने कथित चोरी की जानकारी मिलने के बाद तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना अपनी गलती माना है, एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, ''इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पूछताछ के दौरान क्या हुआ, यह गोपनीय है और इसे साझा नहीं किया जा सकता।'' सूत्रों ने स्वीकार किया कि ट्रस्ट को सात जून से पहले ही चढ़ावे के कथित गबन की जानकारी हो गई थी। इसी दिन यह मामला पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया था। चंपत राय के कुछ समर्थकों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि वह ''पूरी तरह निर्दोष'' हैं और कथित गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई की थी।

वे हालांकि यह नहीं स्पष्ट कर सके कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी 25 जून को ही क्यों दर्ज की गई, जबकि पांच जून को एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से कथित रूप से दान की राशि से भरा बैग बरामद होने का दावा किया गया था।

एनआईए ने 2023 रामनवमी हिंसा में टीएमसी की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार के पति को गिरफ्तार किया

कोलकाता/भाषा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाकिर अली को मार्च-अप्रैल 2023 में राज्य भर में राम नवमी रैलियों के दौरान भड़काई गई सार्वजनिक हिंसा की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। शाकिर अली पार्टी की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार के पति हैं। अधिकारी ने बताया कि रिसड़ा नगरपालिका के वार्ड संख्या 4 के पार्षद अली को रिसड़ा में उनके घर से हिरासत में लिया गया। मंगलवार सुबह एनआईए के एक दल ने सीआरपीएफ जवानों के साथ वहां तलाशी अभियान चलाया था। छापे के दौरान एनआईए अधिकारियों की पांच घंटे की पूछताछ में अली के जवाबों में विसंगतियां मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने कहा, ''शाकिर अली को 2023 के रिसड़ा राम नवमी हिंसा मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

त्रुटियों से भरी पाठ्यपुस्तक के कारण बच्चों का भविष्य दांव पर: नवीन पटनायक

भुवनेश्वर/भाषा। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मंगलवार को ओडिशा में स्कूल के विद्यार्थियों को त्रुटियों से भरी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे 'बच्चों के भविष्य की नींव हिल गई है'। पूर्व मुख्यमंत्री ने पाठ्यपुस्तकों को बच्चों के लिए 'सच्चाई का पहला स्रोत' बताते हुए कहा, जब इस भरोसे से समझौता होता है, तो इसका नुकसान केवल छपाई की गलती तक सीमित नहीं रहता।

सरकारी विद्यालयों के कुछ शिक्षकों ने पहली से आठवीं कक्षा तक की नई पाठ्यपुस्तकों में 1,600 से अधिक त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया था, जिनमें वर्तनी संबंधी गलतियां और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम गलत लिखे जाने जैसी गलतियां शामिल हैं। विपक्षी बीजद इस मामले में ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग कर रही है। पार्टी के युवा और छात्र संगठनों ने मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पटनायक ने पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, स्कूल की पाठ्यपुस्तकें केवल किताबें नहीं होतीं। हर बच्चे के लिए वे सच्चाई का पहला स्रोत होती हैं। एक बच्चा कई बातों पर सवाल उठा सकता है, लेकिन स्कूल की पाठ्यपुस्तक में छपे शब्दों पर नहीं।

मोदी ने आदिवासी नायकों को इतिहास में उनका उचित स्थान दिया, कांग्रेस ने नजरअंदाज किया : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'हूल दिवस' के मौके पर मंगलवार को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को ''इतिहास में उनका उचित स्थान'' दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया और आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को जान-बूझकर नजरअंदाज किया। हूल दिवस 1855-56 में 30 जून को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संथाल विद्रोह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

हूल दिवस के मौके पर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिदो और कान्हू मुर्मू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रमुखता से सामने लाने का काम किया है।

सिन्हा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''आज हूल दिवस पर, मैं संथाल समुदाय के दो बहादुर भाइयों सिदो और कान्हू को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 30 जून, 1855 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक का नेतृत्व किया था।'' उन्होंने कहा, ''जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो कांग्रेस सरकारों ने हमेशा हमारे आदिवासी योद्धाओं के योगदान को नज़रअंदाज़ किया और ऐसा जान-बूझकर किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने हमारी आदिवासी विरासत और परंपरा को सामने लाने की पुरज़ोर कोशिश की।''

मिज़ोरम शांति समझौता सुलह और शांति स्थापना का वैश्विक मॉडल : राज्यपाल

आइजोल/भाषा। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने मंगलवार को ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते की प्रशंसा करते हुए इसे सफल विवाद समाधान और शांति स्थापना के बेहतरीन वैश्विक मॉडल में से एक बताया। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि वे उस मुश्किल से हासिल हुई शांति को बनाए रखें और मज़बूत करें, जिसने पिछले चार दशकों में राज्य की कायापलट कर दी है।

मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के 40 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह शांति समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और सुलह, दूरदर्शी नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। इस कार्यक्रम का आयोजन जोरम रिसर्च फ़ाउंडेशन और आइजोल क्लब ने संयुक्त रूप से किया था।

राज्यपाल ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से मिजोरम मोटे तौर पर अशांति से मुक्त रहा है, जो यहां के लोगों के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है और इसे शांति-स्थापना के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल बनाता है। उन्होंने कहा,''बिना किसी संशय प्रगति हो रही है। इस शांति प्रक्रिया में सभी शामिल हैं और यह उपलब्धि मिजोरम के लोगों की है।''

राज्यपाल ने कहा कि इस समझौते ने दो दशकों से चल रहे उग्रवाद को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और राज्य में स्थायी शांति, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

बंगाल सरकार आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 350 करोड़ रु. का पैकेज तैयार कर रही : शुभेंदु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुकुटमणिपुर/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय विकास विभाग को आदिवासी बहुल इलाकों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया है।

शुभेंदु बांकुरा जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मुकुटमणिपुर में 'हुल दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह दिवस ब्रिटिश राज के खिलाफ 1855 के ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। शुभेंदु ने कहा, हमने अपने जनजातीय विकास विभाग को राज्य में आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का

आरोप लगाते हुए कहा कि उसने (ममता सरकार) 'पश्चिमांचल विकास विभाग' के लिए निधि नहीं दी थी। यह विभाग राज्य के पश्चिमी जिलों में आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था।

शुभेंदु ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के पश्चिमी हिस्से में आदिवासी-बहुल जंगलमहल इलाके के 75 ब्लॉक में तत्कालीन तृणमूल सरकार ने अलग-अलग कार्यों के लिए सिर्फ छह करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा, हमने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस विभाग के लिए 1,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। शुभेंदु ने कहा कि जंगलमहल इलाके में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम स्वास्थ्य देखभाल और जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे।

ओडिशा: प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर एक नाबालिग स्कूली छात्रा को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

भद्रक/भाषा। ओडिशा के भद्रक जिले में 22 वर्षीय एक विवाहित युवक ने प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर एक नाबालिग स्कूली छात्रा के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना भद्रक जिले के धामनगर ब्लॉक के धुसुरी थाना क्षेत्र के फतेपुर में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान धमघाटपुर गांव निवासी दिलीप जेना के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले से ही एक अन्य महिला से विवाहित है और वह छात्रा को अपने प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और जब लड़की ने बार-बार उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो आरोपी ने स्कूल जाते समय रास्ते में उसे कथित तौर पर रोक लिया, उसके ऊपर पेट्रोल डाल कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की।

कोलकाता पुलिस ने धर्मतला में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की

कोलकाता/भाषा। कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को धर्मतला इलाके में 60 दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस की सालाना '21 जुलाई शहीद दिवस' रैली का पारंपरिक आयोजन स्थल भी शामिल है। पुलिस ने यह कदम संभावित हिंसक प्रदर्शनों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उठाया है, जिनसे कानून-व्यवस्था व यातायात में बाधा आ सकती है।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर मंगलवार को यह आदेश जारी किया। यह आदेश दो जुलाई से 30 अगस्त तक या अगली सूचना तक लागू रहेगा। ये पाबंदियां बहुबाजार थाने, हेयर स्ट्रीट थाने व मुख्यालय यातायात गार्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों पर लागू होंगी। ये इलाके केसी दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस व उसके आस-पास के क्षेत्रों तक फैले हैं, लेकिन इनमें बेंटिंक मार्ग शामिल नहीं है। पारंपरिक रूप से तृणमूल की 'शहीद दिवस' रैली विक्टोरिया हाउस के सामने वाली जगह पर होती रही है।

भारत ने पहले महिला अंडर 19 वनडे में श्रीलंका को 120 रन से हराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुडुचेरी/भाषा। भारत ने बेहतरीन हरफनमौला खेल का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को पहले अनधिकृत अंडर 19 महिला वनडे में श्रीलंका को 120 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आठ विकेट पर 279 रन बनाये । सलामी बल्लेबाज इरा जाधव ने 83 रन बनाये जबकि निधि महतो ने अर्धशतक जमाया । जवाब में श्रीलंका की टीम 48 . 5 ओवर में 159 रन पर आउट हो गई। जाधव ने 104 गेंद की अपनी पारी में बीच के ओवरों में कई उपयोगी साझेदारियां की । निधि ने 51 गेंद में 54 रन जोड़े । कप्तान भाविका अहिरे ने 42 और वी प्रतीक्षा ने 21 रन बनाये ।

श्रीलंका के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और पहले दस ओवर में ही उसके तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे । मानुदी नानायाक्कारा ने 47 और लिमांसा तिलकरत्ना ने 30 रन बनाये ।

बंगाल के अनुकूल इलाकों में बाघों को दोबारा बसाने की संभावनाओं पर किया जा रहा विचार : भूपेंद्र यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार वैज्ञानिक योजना के जरिए पश्चिम बंगाल के उपयुक्त इलाकों में बाघों को फिर से बसाने पर विचार कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत के विकास एजेंडे का एक अहम

हिस्सा बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री यादव ने राजस्थान के सरिस्का में बाघों को फिर से बसाने की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल में, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, उपयुक्त जगहों पर बाघों को फिर से बसाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरिस्का में 2008 में एक भी बाघ नहीं बचा था लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

यादव ने देश में पर्यावरण संरक्षण से हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से बाघ अभयारण्य की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है, जबकि एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2026 में 891 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने भारत की जैव-विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया की कुल भूमि में भारत की हिस्सेदारी महज 2.4 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद यह दुनिया की सभी दर्ज प्रजातियों में से सात से आठ प्रतिशत का घर है। उन्होंने कहा, ''हमारी सभ्यता ने प्रकृति को हमेशा शोषण के संसाधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी साझा विरासत के तौर पर देखा है जिसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।''

सुविचार

विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अभाव की मानसिकता छोड़ें

मुंबई के एक मॉल में एक रुपए में कपड़े बेचे जाने की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा होना कोई सामान्य घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उक्त मॉल के बाहर जो लोग खरीदारी करने उमड़े, उनमें से ज्यादातर वे थे, जिनके घरों की अलमारियां पहले ही कपड़ों से भरी पड़ी थीं। यह आदत एक खास मानसिक स्थिति के कारण पैदा होती है, जिसे समझना और सुधार करना जरूरी है। इसे 'स्कैरसिटी माइंडसेट' यानी 'अभाव की मानसिकता' कहा जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति कोई चीज सबसे पहले हासिल करना चाहता है। उसे लगता है कि 'यह चीज कहीं खत्म न हो जाए! यह खत्म हो, उससे पहले मैं अपना हिस्सा ले लूं।' वह दूसरों की परवाह नहीं करता है। अक्सर यह हालत चीजों की कमी होने से नहीं, बल्कि लोगों की नीयत की वजह से पैदा होती है। इससे अनुशासन का अभाव झलकता है। जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो विदेशों में हमारे देश की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। हमें ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। विवाह कार्यक्रमों में ऐसे नजारे खूब देखने को मिलते हैं। कई लोग अपनी प्लेट जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बाद धरती पर खाना नहीं मिलेगा! वे अपनी बारी के लिए दूसरों को धक्का मारने से भी गुरेज़ नहीं करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो एक उम्मीदवार ने अपनी जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं के लिए लड्डू मंगवाए थे। उन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इस तरह टूटा कि साबुत लड्डू दो-चार लोगों के हाथ ही आए होंगे। सड़क पर गिरे लड्डुओं के लिए भी छीना-झपटी मच गई थी। वहां मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में पर्याप्त खाना रहा होगा। वे मिठाई खरीदकर खाने में समर्थ थे। फिर 'अभाव की मानसिकता' का ऐसा प्रदर्शन क्यों?

ऐसे लोग हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि हम कहीं दूसरों से पीछे न रह जाएं। वे हर उपलब्धि की दूसरों से तुलना करते हैं। उन्हें डर रहता है कि अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भयंकर अभावों से जूझ रहा है और वह ऐसा प्रदर्शन करे तो इसे काफी हद तक स्वाभाविक माना जा सकता है, लेकिन जो उससे बहुत बेहतर स्थिति में है, वह भी उसी हरकत को दोहराए तो इसे मामूली बात नहीं मानना चाहिए। कई लोग जब सिनेमा हॉल में दाखिल होते हैं तो अपनी सीट तक पहुंचने के लिए बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कोई उनकी सीट पर न बैठ जाए या उठाकर ही न ले जाए! वे सीट पर बैठते ही राहत की सांस लेते हैं, जैसे किसी बादशाह का सिंहासन जीत लिया। इधर फिल्म पूरी हुई नहीं कि वापस यही सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये लोग सबसे पहले बाहर निकलने के लिए मशक्कत करने लगते हैं। अगर सबसे पहले बाहर निकल भी गए तो क्या हो जाएगा? क्या इससे कोई मेडल मिल जाएगा? जब इतनी जल्दी थी तो आए ही क्यों? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं – यह इन्हें भी मालूम नहीं है। वास्तव में, यह 'अभाव की मानसिकता' का एक और उदाहरण है। ये इस आदत के वशीभूत होने के कारण अपनेआप ऐसा करने लगते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि हममें यह आदत हमेशा से नहीं थी। कालांतर में विदेशी आक्रांता यहां शासन करने लगे और चीजों की कृत्रिम किल्लत पैदा होने लगी थी। इससे लोगों में यह आदत विकसित होती गई कि 'सबसे पहले मुझे मिले ... फिर किसी की परवाह नहीं है।' धीरे-धीरे यह आदत कई जगह दिखाई देने लगी। यह कोई सार्वभौमिक प्रवृत्ति नहीं है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, डेनमार्क और जापान जैसे देशों में ऐसी घटनाएं न के बराबर होती हैं। अगर वे लोग अपने सार्वजनिक व्यवहार में अनुशासन और शालीनता दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? हमें 'अभाव की मानसिकता' छोड़नी चाहिए।

ट्वीटर टॉक

सिविल लाइंस के सभी प्यारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मिले इस अपार स्नेह, उत्साह और दिल से स्वागत के लिए आप सभी का दिल से और सच्चे दिल से शुक्रिया! आप सभी का यही जुड़ाव और भरोसा मुझे राज्य की लगातार सेवा के लिए नई एनर्जी देता है।

-भजनलाल शर्मा

करौली जिले के टोडाभीम थाना इलाके में टूटे हुए 11 केवी तार में उलझकर और करंट की चपेट में आकर तीन लोगों के ज़िंदा जलने की खबर बहुत दिल दहला देने वाली है।इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, और उन ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

-अशोक गहलोत

आज आपके पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर, मेरा दिल भारी हो रहा है और मैं आदर से हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रिय टीचर धात्री मेनेंजेश, जिन्होंने मुझे स्कूल के दिनों में अक्षर और ज़िंदगी के सबक सिखाए। मैं आपके प्यारे स्टूडेंट के तौर पर आखिरी सलाम करने आया हूँ...।

डीके शिवकुमार

प्रेरक प्रसंग

प्रेमचंद की गाय

उन दिनों प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक मुंशी प्रेमचंद गोरखपुर में अध्यापक थे। उन्होंने अपने यहाँ गाय पाल रखी थी। एक दिन चरते-चरते उनकी गाय वहाँ के अंग्रेज़ जिलाधीश के आवास के बाहरवाले उद्यान में घुस गई। अभी वह गाय वहाँ जाकर खड़ी ही हुई थी कि वह अंग्रेज़ बंदूक लेकर बाहर आ गया और उसने गुस्से से आग बबूला होकर बंदूक में गोली भर ली।उसी समय अपनी गाय को खोजते हुए प्रेमचंद वहाँ पहुँच गए। अंग्रेज़ ने कहा कि 'यह गाय अब तुम यहाँ से ले नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने जानवर को मेरे उद्यान में घुसा दिया। मैं इसे अभी गोली मार देता हूँ, तभी तुम काले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि हम यहाँ हुकूमत कर रहे हैं।' और उसने भरी बंदूक गाय की ओर तान दी। प्रेमचंद ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, 'महोदय! इस बार गाय पर मेहरबानी करें। दूसरे दिन से इधर नहीं आएगी। मुझे ले जाने दें साहब। यह ग़लती से यहाँ आई।' फिर भी अंग्रेज़ झल्लाकर यही कहता रहा, 'तुम काला आदमी ईडियट हो – हम गाय को गोली मारेगा।' और उसने बंदूक से गाय को निशान बनाना चाहा।

सामयिक

वास्तव में, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी एक बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है। ब्रिटेन जैसी सख्ती बरतने की नौबत हमारे देश में पैदा न हों, इससे बचने के लिए हम सबको पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। क्योंकि आज हम जो भी कदम उठाते हैं या जो भी बदलाव चुनते हैं, उसका सीधा असर हमारे और आने वाले कल के बच्चों के जीवन पर पड़ता है।

आखिरी उपाय बनाम पर्यावरण - अनुकूल दृष्टिकोण

डॉ. आशीष वशिष्ठ

मोबाइल : 94 5100 5200

आमतौर पर ठंडा रहने वाला यूरोप अब भट्टी की तरह जल रहा है। तापमान हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर की बिक्री बढ़ गई है। लेकिन ब्रिटेन में इसका उलट हो रहा है। वहां गर्मी बढ़ने के बावजूद जिन घरों में एसी लगा है, उन घरों में रहने वालों को एसी हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि एसी से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इनका इस्तेमाल सिर्फ 'आखिरी उपाय' के तौर पर ही किया जाना चाहिए। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब ब्रिटेन हीटवेव की चपेट में हैं, जिसके कारण स्कूल बंद कराने पड़े हैं, ट्रेनें रोक दी गई हैं, 4 हजार से ज्यादा ऑपरेशन टलने का खतरा है, और वहां के मौसम विभाग ने 'रिस्क-टू-लाइफ' का रेड अलर्ट जारी किया है। ये सारी सख्तियां 'नेट जीरो पॉलिसी' के तहत हो रही हैं। पॉलिसी के अनुसार 'एक्टिव कूलिंग' की इजाजत तभी दी जानी चाहिए जब 'पैसिव कूलिंग' के सभी तरीके आजमा लिए गए हों। यानी, एसी का इस्तेमाल तभी हो सकता है, जब और कोई उपाय न बचा हो।

कल्पना कीजिए ब्रिटेन की तरह भारत में एसी हटाने के आदेश जारी होते या जबरदस्ती की जा रही होती तो हालात कैसे होते। निश्चय ही, हालात काफी बुरे होते। भारत जैसे गर्म देश में एसी आज जरूरत बन चुके हैं, लेकिन इनका पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में एसी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर प्राय: उतनी चर्चा नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। भारत में गर्मी हर साल नये रिकार्ड बना रही है। इस साल भारत भीषण गर्मी का वैश्विक केंद्र बन गया है। विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों में से 90 से ज्यादा भारत में है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 1901 में विस्तृत रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2024 भारत का सबसे गर्म साल था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच भारत में लू लगने के कारण लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई।

भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एसी बाजार है, लेकिन मौजूदा समय में केवल सात फीसदी घरों में ही एसी है। साल 2024 में रिकॉर्ड 1.4 करोड़ 2025 में लगभग 1.5 करोड़ एयर कंडीशनर यूनिटों की बिक्री हुई। अनुमान है कि सदी के मध्य तक घरों में इसके लगाए जाने में नौ गुना वृद्धि का अनुमान है। भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण पिछले कुछ सालों में एसी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और अब यह लग्जरी के बजाय एक आवश्यकता बन गया है। हालांकि एसी की बिक्री बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ेगी, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले कोयले को जलाकर पैदा की जाती है। बढ़ती ऊर्जा की मांग पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन को तीन गुना बढ़ाना होगा। 1.4 अरब की आबादी वाला देश पहले से ही जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दफ्तरों और घरों में ज्यादा एसी लगने से उससे निकलने वाली गर्म हवा में भी बढ़ोतरी होगी। एसी यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट और उन्हें चलाने वाली कोयले से पैदा बिजली ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाते हैं। एसी का व्यापक इस्तेमाल घर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालकर बाहर का तापमान भी बढ़ाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और यूएन-हैबिटेट के रिसर्चों से पता चलता है कि एसी के अंदर गर्मी पैदा करने वाली मोटर खुद शहरी क्षेत्रों में तापमान को एक डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ा सकती हैं। वहीं विंडो और स्प्लिट एसी प्रक्रिया के दौरान जो पानी बाहर निकालते हैं, वह अक्सर बर्बाद होता है। इसके अलावा, कूलिंग टावरों में लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जो जल संकट को बढ़ाता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कूल कोएलिशन के मुताबिक 2050 तक भारत के उत्सर्जन में एयर कंडीशनिंग का योगदान एक चौथाई होगा और देश भर में बिजली की अधिकतम मांग का लगभग आधा हिस्सा एयर कंडीशनिंग के कारण होगा। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र के जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए कोएलिशन की ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत में हाल के दिनों में घरों, कार्यालयों, होटलों व मॉल तक में एसी का उपयोग बेतहाशा बढ़ा है। जिसके चलते गर्मियों के पीक सीजन में बिजली की खपत चरम पर पहुंच जाती है। देश में भीषण गर्मी और लू की स्थिति ने बिजली की खपत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार ने एसी की पहचान बिजली की बढ़ती खपत के लिये जिम्मेदार खलनायक के रूप में की है।

मई 2026 में भारत की बिजली खपत 11.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164.98 अरब यूनिट पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार योजना बना रही है कि घरों, होटलों व कार्यालयों में बीस डिग्री से अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस के बीच इस्तेमाल होने वाले इस उपकरण की कूलिंग रेंज को मानकीकृत किया जाए।

हमें स्वयं से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि हमारे शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? हम इस बढ़ते तापमान से नागरिकों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अंधाधुंध-अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्य भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। हमने चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तो बना दिए लेकिन शहरों में हरियाली का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। जिससे हवा का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित हो रहा है। विकास के नाम पर जो सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति नये पेड़ लगाकर नहीं की जाती है। क्या हम घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाये रखने वाली भवन निर्माण तकनीक नहीं अपना रहे हैं? यदि उष्मारोधी भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को कम बिजली खपत से भी राहत मिल सकती है। यदि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तो सड़कों पर निजी वाहनों का उपयोग कम होने से वाहनों के गर्मी बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। वहीं भवन निर्माण में छतों को ठंडा रखने वाली तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

इन उपायों से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाकर और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करके हम तापमान को कम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को सुबह जल्दी या शाम के ठंडे समय में करने से दिन की चिलचिलाती धूप में एसी चलाने की आवश्यकता घट जाती है। इस कदम से ऊर्जा की बचत के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। कार्यस्थल और घर में एसी के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

वास्तव में, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी एक बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है। ब्रिटेन जैसी सख्ती बरतने की नौबत हमारे देश में पैदा न हों, इससे बचने के लिए हम सबको पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। क्योंकि आज हम जो भी कदम उठाते हैं या जो भी बदलाव चुनते हैं, उसका सीधा असर हमारे और आने वाले कल के बच्चों के जीवन पर पड़ता है।

नजरिया

डॉक्टर की मुस्कुरहट में छिपा है मरीज़ का इलाज

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

दरअसल एक डॉक्टर का कार्य मरीजों के हित में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होता है, लेकिन कई बार लाख कोशिश के बावजूद वे मरीज को सन्तुष्ट नहीं कर पाते। कई बार मरीज के परिजन अस्पताल के खर्चे को देखकर भड़क जाते है वह भी तब जब मरीज बजाय ठीक होने के अधिक बीमार होता चला जाता है। उस समय परिजन समझते है अस्पताल अपने खर्चे निकलने में जुटा है और उसे मरीज के स्वास्थ्य की चिंता कम है।

भारत में डॉक्टर विधान चन्द्र राय की समृति में एक जुलाई को प्रति वर्ष डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है डॉक्टर की मुस्कुरहट में छिपा है मरीज़ का इलाज। डॉक्टर को धरती का भगवान माना और स्वीकार किया जाता है। पीड़ित मानवता की सेवा के कारण समाज में डॉक्टरों का विशेष आदर और सत्कार है। वर्तमान में डॉक्टरी ही एक ऐसा पेशा है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं। इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी डॉक्टरों पर है। डॉक्टर्स डे स्वयं डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह उन्हें अपने चिकित्सकीय प्रैक्टिस को पुनर्जीवित करने का अवसर देता है। डॉक्टर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ज़रूरत के समय में चिकित्सा देखभाल, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। डॉक्टरों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

वे न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता भी फैलाते हैं। एक डॉक्टर रोग की पहचान करता है, उचित दवा देता है और मरीज को सही जीवनशैली अपनाने की सलाह भी देता है। डॉक्टरों के बिना किसी भी समाज की कल्पना अधूरी है, क्योंकि स्वस्थ समाज ही किसी देश की प्रगति की नींव होता है।

इस डॉक्टर दिवस पर, आइए हम उनकी निस्वार्थता, विशेषज्ञता और समाज की भलाई के प्रति अटूट समर्पण के लिए अपना आभार व्यक्त करें। डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों का न सिर्फ इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी देते हैं। इसलिए उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते वक्त बहुत से डॉक्टर भी संक्रमित हो गए। अनेक अकाल मौत का शिकार भी हुए। फिर भी जनता की सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ है। ऐसा देखा गया है कि इस पावन पवित्र पेशे में भी ऐसे लोग घुस गए हैं जो समर्पण और त्याग के स्थान पर मरीज को लूटने में लग गए है।

विशेषकर निजी और प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना संघर्ष के दौरान सेवा कम और लूट पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित रखा। इन अस्पतालों के अनेक लोग पकडे भी गए। आज आवश्यकता इस बात कि है की इस बदले हुए स्वरुप को जन कल्याण की दिशा में परिवर्तित कर चिकित्स्कीय पेशे के सम्मान की रक्षा कर खोये हुए गौरव को फिर बहाल कर जनता के विश्वास को जीता किया जाए। भारत में आम आदमी छोटी-मोटी बीमारियां होने पर दवाखाना अथवा डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता है। सर्दी-जुकाम, खांसी-बुखार आदि मौसमी बीमारियों के दौरान घरेलू उपचार पर वह ज्यादा ध्यान देता है। जब मर्ज बढ़ जाता है और बीमारी बिगड़ जाती है, तब वह दवाखाने की शरण में आता है और डॉक्टर को भगवान मानकर अपने परिजन को स्वस्थ करने की याचना करता है। कमोबेश हमारे देश के आम आदमी की यही स्थिति है।

आज हमें निष्पक्ष भाव से डॉक्टर और मरीज के बीच पनपे अविश्वास की चुनौतियों पर विचार करना होगा। दरअसल इन दिनों डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई बार मरीज बेहतरीन इलाज मिलने के बावजूद भड़क जाते हैं और डॉक्टर या हॉस्पिटल को नुकसान भी पहुंचा देते हैं।

ऐसा हाल के वर्षों में कई जगह देखने को मिला है। ऐसी खबरें आपने भी अखबारों या टीवी पर पढ़ी या देखी होंगी। दरअसल एक डॉक्टर का कार्य मरीजों के हित में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होता है, लेकिन कई बार लाख कोशिश के बावजूद वे मरीज को सन्तुष्ट नहीं कर पाते। कई बार मरीज के परिजन अस्पताल के खर्चे को देखकर भड़क जाते है वह भी तब जब मरीज बजाय ठीक होने के अधिक बीमार होता चला जाता है। उस समय परिजन समझते है अस्पताल अपने खर्चे निकलने में जुटा है और उसे मरीज के स्वास्थ्य की चिंता कम है। मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास की भावना का अभाव है जिसके कारण अस्पतालों में आये दिन मारपीट की घटनाएं होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि मरीज डॉक्टर पर विश्वास करें वहीँ डॉक्टर का भी यह कर्तव्य है कि वह मरीज और उसके परिजनों को विश्वास में लेकर ही अपने कार्य को अंजाम दें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

संबोधन

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मुंबई में मंगलवार को शिवसेना विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए महायुति उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

जापान की प्रधानमंत्री तकाइची आर्थिक सुरक्षा, निवेश पर मोदी के साथ करेंगी वार्ता

टोक्यो/भाषा। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची इस हफ्ते अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता में आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगी। जापान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत का दौरा करेंगी और अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान-भारत शिखर बैठक करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि तकाइची के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना है, जो 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ''बेहद जरूरी'' है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता ''अगले दशक के लिए जापान-भारत की साझा दृष्टि'' के तहत ''पारस्परिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने'' पर चर्चा करेंगे। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के दौरान साझा दृष्टि की घोषणा की गई थी। मंत्रालय के अनुसार, वार्ता में ''ऊर्जा सहित आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्रों, और साथ ही निवेश व नवाचार के जरिए आर्थिक विकास'' पर चर्चा की जाएगी। तकाइची की यह यात्रा अगस्त 2025 में मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है, जिस दौरान दोनों देशों ने अगले दशक के लिए जापान-भारत संयुक्त दृष्टि पत्र जारी किया और जापान ने आगामी दशक में भारत में 10,000 अरब येन (जापानी मुद्रा) के निवेश का लक्ष्य घोषित किया।

'डियर जाहिरा, विद लव': विभाजन पर आधारित मार्मिक प्रेम कहानी

नई दिल्ली/भाषा। बंटवारे के उथल-पुथल भरे दौर पर इम्तियाज अली की फिल्म ''में वापस आऊंगा'' के सिनेमाघरों में दर्शकों की भावनाओं को झकझोरने के बीच लेखक सचिन एनजी की किताब ''डियर जाहिरा, विद लव'' के जरिए इस विषय को साहित्य में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह पुस्तक विभाजन के बाद की वास्तविक घटना से प्रेरित एक मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है।

'ग्रेपवाइन बुक्स' द्वारा प्रकाशित यह उपन्यास मुख्य किरदारों, गुलाम अली और ज़ाहिरा रजा की जिंदगी के जरिए यह दिखाता है कि कैसे ''प्यार सरहदों के पार भी कायम रहता है और जुदाई, तड़प और उम्मीद की एक बेहद मानवीय कहानी को जीवंत करता है।'' लेखक ने एक बयान में कहा, ''लोग समझते हैं कि विभाजन 1947 में हुई एक घटना भर थी, लेकिन उसका दर्द आज भी जिंदा है। जब भी सीमा के उस पार बसे अपने भाई की याद में किसी बहन की आंखें नम होती हैं, तब विभाजन की त्रासदी फिर से महसूस होती है।'' उन्होंने कहा, ''जब भी कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा की ओर रवाना होता है, विभाजन की विरासत सामने आ जाती है। और जब भी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, तब भी विभाजन का प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाई देता है।'' सचिन अली और रजा की कहानी को जीवंत करते हैं, जिनकी जिंदगी 1947 की घटनाओं से बिखर गई थी। सरहद से अलग होने के बाद, अली लाहौर में हिंदू शरणार्थी शिविरों से चिट्ठियां लिखते हैं, जबकि रजा लखनऊ में अनिश्चितताओं के बीच उम्मीद का दामन थामे उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। पुस्तक के विवरण में कहा गया है, ''उनकी कहानी इस बात की मार्मिक याद दिलाती है कि सीमाएं भले ही देशों को बांट दें, लेकिन वे प्रेम और मानवीय रिश्तों के बंधनों को हमेशा कमजोर नहीं कर सकतीं।''

प्रकाशक के अनुसार, भावनाओं से भरे पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से कही गई ''डियर जाहिरा, विद लव'' दो ऐसे लोगों की कहानी को जीवंत करती है, जिनका जीवन भारत-विभाजन की उथल-पुथल से गहराई से प्रभावित हुआ।

प्रदर्शन

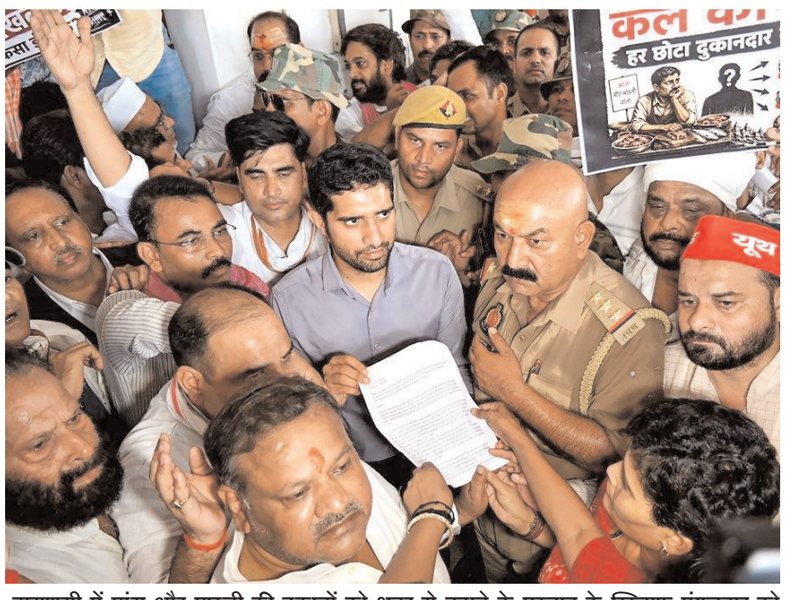

वाराणसी में मांस और मछली की दुकानों को शहर से हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी , समाजवादी पार्टी के नेता और विभिन्न व्यापारी संगठनों के सदस्य।

बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई

ढाका/भाषा। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक सहयोगी को 2024 के प्रदर्शनों के दौरान ''मानवता के खिलाफ अपराध'' के आरोप में मंगलवार को 10 साल की जेल की सजा सुनाई।

वामपंथी विचारधारा के नेता हसनुल हक इनु ने 2012 से 2018 तक शेख हसीना की गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन इसके बाद उनका उस शासन से कोई संबंध नहीं रहा।

वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के योद्धा और जातीय समाजतांत्रिक दल के अध्यक्ष हसनुल हक इनु पर आरोप है कि उन्होंने 2024 के आंदोलन के दौरान अपने गृह जिले कुश्तिया में पुलिस को छह लोगों की हत्या करने का आदेश दिया, प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए उकसाया और अगस्त 2024 में भारत चली गईं शेख हसीना के साथ टेलीफोन के जरिए संपर्क बनाए रखा। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने इनु को सज़ा सुनाई, जिन पर आठ अलग-अलग आरोपों में मुक़दमा चल रहा था। अन्य आरोपों में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ ज्यादती के लिए उकसाना और सेना की तैनाती, कर्फ्यू लगाने और ''देखते ही गोली मारने'' के आदेशों से जुड़े फ़ैसलों में सीधे तौर पर शामिल होना शामिल था। न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला उस समय सुनाया, जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस इनु को जेल से अदालत लेकर आई।

न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा, ''हम इस फैसले से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। हमारा मानना है कि उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए था। हम निश्चित रूप से इस निर्णय के खिलाफ (उच्चतम न्यायालय में) अपील करेंगे।''

बंगाल में बाघों को दोबारा बसाने की संभावनाओं पर किया जा रहा विचार : भूपेंद्र यादव

कोलकाता/नई दिल्ली/ भाषा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार अब राज्य के उपयुक्त इलाकों में बाघों को फिर से बसाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने राजस्थान के सरिस्का में बाघों को दोबारा बसाने की सफलता का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह 'रॉयल बंगाल टाइगर' की धरती के लिए भी इसी तरह के दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। सरिस्का में 2008 में एक भी बाघ नहीं बसा था लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

यादव ने कहा, ''सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक योजना और विशेषज्ञों के साथ गंभीर विचार-विमर्श से, उपयुक्त इलाकों में बाघों को फिर से बसाने की संभावना तलाशी जा रही है, जिससे जैव-विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा, दोनों को मजबूती मिलेगी।''वह कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 111वें स्थापना दिवस पर आयोजित 'पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन- 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने रेखांकित किया कि 2014 से भारत के पर्यावरण शासन में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले का तरीका ज्यादातर प्रतिक्रियाशील और नियामकीय था, लेकिन अब देश सक्रिय भूमिका निभा रहा है और पर्यावरण व जैव-विविधता पर वैश्विक एजेंडा तय करने में मदद कर रहा है। यादव ने कहा, ''संरक्षण को अब पर्यावरण से जुड़ी कोई अलग-थलग चिंता नहीं माना जाता, बल्कि यह सतत विकास और 'विकसित भारत' के हमारे दृष्टिकोण का एक अहम स्तंभ है।''

उन्होंने कहा कि 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा अनुकूल अवसंरचना गठबंधन , इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वैश्विक जैवईंधन गठबंधन जैसी पहलों और जलवायु न्याय की पुरजोर वकालत के जरिए भारत ने यह साबित कर दिया है कि पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी और आर्थिक प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। यादव ने कहा, ''आज हम केवल दुनिया की पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि वैश्विक समाधान तैयार करने में भी मदद कर रहे हैं।''

ऑटिज्म बीमारी नहीं, समझ और अपनापन चाहिए : ईशा सिंह

मुंबई/एजेन्सी

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह इन दिनों अपने आने वाले शो 'जूही मुई' को लेकर चर्चा में हैं। इस शो में वह अपने करियर का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने जा रही हैं। ईशा इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाली लड़की 'जूही' की भूमिका में नजर आएंगी। अपने इस किरदार की तैयारी और ऑटिज्म को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों पर अभिनेत्री ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में लोग ऑटिज्म को बीमारी समझते हैं, जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। को दिए एक इंटरव्यू में ईशा सिंह ने कहा, आज भी बहुत से लोग ऑटिज्म को सही तरीके से नहीं समझते। जागरूकता की कमी पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी देखने को मिलती है। मेरे अपने दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी नहीं है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग इस विषय को समझें और इसके बारे में सही जानकारी हासिल करें।ईशा सिंह ने कहा, ऑटिज्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे बीमारी मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। कुछ माता-पिता यह सोचते हैं कि ऑटिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जबकि यह पूरी तरह गलत धारणा है। ऑटिज्म न तो संक्रामक है और न ही यह किसी तरह की बीमारी है। अभिनेत्री का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले बच्चे अक्सर बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और प्यार करने वाले होते हैं। उन्हें समाज से सहानुभूति नहीं बल्कि समझ और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के साथ दुनिया में आता है।अपने नए शो में निभाए जा रहे किरदार को लेकर ईशा सिंह ने कहा, यह मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रोल है। चूंकि यह एक बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए मैंने इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा उद्देश्य ऑटिज्म से जुड़े लोगों की भावनाओं और व्यवहार को पूरी ईमानदारी के साथ दर्शकों तक पहुंचाना था। ईशा ने कहा, इस किरदार की तैयारी के दौरान मैंने ऑटिज्म पर आधारित कई इंटरव्यू देखे, विशेषज्ञों और लोगों से बातचीत की, इस विषय पर काफी रिसर्च की और कई किताबें भी पढ़ीं। यह सीखने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जूही का किरदार निभाते हुए मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैंने अपने स्टडी, लोगों के अनुभव और अपनी व्यक्तिगत समझ को मिलाकर इस किरदार को तैयार किया है।अभिनेत्री ने बताया, जूही के किरदार के लिए मुझे अपने चलने, बोलने, बैठने, प्रतिक्रिया देने और भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर भी बारीकी से काम करना पड़ा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले लोग हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसे सामान्य तरीके से व्यक्त कर पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अभिनय में किसी तरह का दिखावा नहीं रखा, बल्कि छोटे-छोटे हाव-भाव और स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया।

अजय देवगन की 'चौहान' साम्प्रदायिक राजनीति के लिए राजपूत पहचान को हथिया रही : क्षत्रिय परिषद

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेता अजय देवगन की नई फिल्म ''चौहान'' के विवादास्पद 'टीजर' पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोमवार को राजपूत संगठन क्षत्रिय परिषद ने कहा कि ऐतिहासिक स्मृति का इस्तेमाल साम्प्रदायिक गोलबंदी करने के लिए नहीं होना चाहिए और इसके निर्माताओं को ''जाति एवं साम्प्रदायिक भावनाएं'' भड़काने के लिए राजपूत नाम के उपयोग से परहेज करना चाहिए।

फिल्म की आलोचना कश्मीर विवाद को दिखाने के तरीके और 'पेलेट गन' से ''बहुत कम नुकसान होने'' का दावा करने को लेकर की गई है।

तीन दिन पहले जारी किये गए फिल्म के 'टीजर' में देवगन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह भीड़ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 'टीजर' की एक पंक्ति है, ''पठानों से कह दो कि चौहान आ रहा है'', जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने की कोशिश बताया है।

अब क्षत्रिय परिषद ने ''चौहान'' नाम के इस्तेमाल पर अपनी बात रखी है।

क्षत्रिय परिषद ने एक बयान में कहा, ''ऐतिहासिक स्मृतियों का इस्तेमाल सांप्रदायिक गोलबंदी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम राजनीतिक हस्तियों, फिल्म निर्माताओं और मीडिया संस्थानों से अपील करते हैं कि वे भारत के अतीत को जिम्मेदाराना तरीके से देखें।''

बयान में फिल्म के निर्देशक नीरज यादव तथा अभिनेता देवगन की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर ''मौजूदा समय की सांप्रदायिक राजनीति के लिए चौहान वंश के नाम का इस्तेमाल करने'' का आरोप लगाया और कहा कि वे राजपूत इतिहास का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, और चुनावी या वैचारिक उद्देश्यों के लिए राजपूत पहचान का दुरुपयोग करने की हर कोशिश को खारिज करते हैं।

क्षत्रिय परिषद ने उन ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया जब राजपूतों और पठानों ने एक साथ और एक-दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी थी।

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कश्मीर में 'पेलेट गन' के सबसे कम उम्र के पीड़ित से जुड़ी एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए एक पोस्ट में लिखा, ''क्या बॉलीवुड इसी चीज का महिमामंडन करना चाहता है? पेलेट गन 'सीमित नुकसान' पहुंचाने वाला हथियार नहीं है। यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। और मुख्यधारा के कश्मीरी, पठान नहीं हैं। कुछ तो शोध कर लिया करो।

ट्रेलर लांच

अभिनेत्री दीया मिर्जा और सनी देओल मुंबई में अपनी आगामी फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होते हुए।

निर्देशक रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी, मांगी गई 20 करोड़ की रंगदारी

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी मिली। इस बार उनसे एक कथित ऑडियो क्लिप के जरिए 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस ऑडियो में कहा गया है कि अगर रकम नहीं दी गई तो इस बार निशाना सीधे रोहित शेट्टी होंगे। इस घटना के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

इस ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर पहले जो फायरिंग हुई थी, वह सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर इस बार मांगी गई रकम नहीं दी गई, तो गोली सीधे फिल्ममेकर को निशाना बनाएगी। जानकारी के मुताबिक, यह लगभग 90 सेकंड लंबा ऑडियो क्लिप शनिवार सुबह रोहित शेट्टी के स्टाफ को मिला था। स्टाफ ने बिना देरी किए इस क्लिप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की जांच प्रक्रिया शुरू की गई।

शुरुआती जांच में ऑडियो में आवाज की पहचान की गई, तो वह कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी सहयोगी शुभम लोणकर से मिलती-जुलती पाई गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुभम लोणकर का नाम पहले भी कई गंभीर मामलों में सामने आ चुका है। वह 2024 में हुई नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और इसी साल रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड है। हालांकि, पुलिस ने अभी इस आवाज की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रोहित शेट्टी के स्टाफ द्वारा यह धमकी भरा ऑडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच चल रही है और ऑडियो क्लिप के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, मामले में आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।

90 के दशक में स्टार एक्टर्स उड़ाते थे मेरा मजाक : रवि किशन

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता और राजनेता रवि किशन ने अपने कठिन समय, संघर्षों और सब्र भरे सफर को याद करते हुए बताया कि 90 के दशक में जो एक्टर्स स्टार बन रहे थे, वे अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें नजरअंदाज करते थे। रियलिटी शो 'अलायंस' में साथी कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए, जिसमें वे खुद भी एक कंटेस्टेंट हैं, रवि ने बड़ी पहचान मिलने से पहले के अपने कई दशकों के सफर के बारे में बताया। रवि ने कहा, अपनी जिंदगी में मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो पहले मेरा मजाक उड़ाते थे। वे 90 के दशक में स्टार बन रहे थे और मैं उन्हें आगे बढ़ते हुए देख सकता था। एक्टर ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए खुद को तैयार करने में कई साल बिताए और हर वो हुनर ङ्घसीखा जो एक एक्टर में होना चाहिए।

उन्होंने कहा, मेरी आवाज अच्छी थी। मुझे घुड़सवारी, एक्शन, उर्दू, हिंदी सब आती थी। मैंने थिएटर किया और डांस भी सीखा था। मैं पूरी तरह तैयार था। इसके बावजूद, मैं पीछे रह गया जबकि बाकी सब आगे बढ़ गए। मैं खुद से कहता रहता था कि अगर उनका समय आया है, तो मेरा भी आएगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेरा समय 34 साल बाद आएगा। रवि किशन ने आगे कहा कि हालात तब

बदले जब उनकी परफॉर्मेंस को जबरदस्त कामयाबी और तारीफ मिली। उन्होंने कहा, फिर जो हुआ, वो 34 साल बाद हुआ। उस साल मैंने 'बेस्ट एक्टर' के सभी अवॉर्ड जीते। मैं उन स्टेज पर खड़ा हुआ जहां मुझे पहले कभी नहीं बुलाया गया था। लोग मुझे कभी नहीं बुलाते थे और सब मेरा मजाक उड़ाते थे। किसी को यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां हूं।

रवि किशन के सब्र, दृढ़ संकल्प और लगन से भरे सफर को सुनकर कंटेस्टेंट्स प्रेरित महसूस कर रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। रवि किशन की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 90 के दशक की शुरुआत में 'पीतांबर,' 'आतंक,' 'आर्मी' और 'जख्मी दिल' जैसी हिंदी फिल्मों से की थी। हालांकि उस दौरान वे कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आए लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने ही उन्हें सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बना दिया। 'सैयां हमार,' 'पंडित जी बताई ना बियाह कब होई' और दूसरी भोजपुरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ वे भोजपुरी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक बन गए। हाल के सालों में रवि ने हिंदी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शानदार परफॉर्मेंस देकर खुद को एक नए रूप में पेश किया है। 'लापता लेडीज' में उनके रोल को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही खूब तारीफ मिली और उन्होंने कई अवॉर्ड्स जीते। 'खाकी: द बिहार चैप्टर' जैसी वेब सीरीज में उनके काम ने एक एक्टर के तौर पर उनकी अलग-अलग तरह के रोल निभाने की काबिलियत को और भी बेहतर ढंग से दिखाया।

मन की निर्मलता और आत्मा की स्वच्छता के लिए मंदिर अति आवश्यक : पंडित महाराज

शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय प्रतिष्ठा हेतु संतों व प्रतिमाओं का हुआ मंगल प्रवेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट, सोलस-2 में गच्छाधिपति जैनाचार्य युगभूषणसूरीश्वरजी (पंडित महाराज), आचार्यश्री अरिहंत सागरजी एवं अनेक साधु साध्वियों की निश्रा में 3 जुलाई से शुरू होने वाले अंजनशलाका प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु संतों का मंगल प्रवेश हुआ। जिनालय के ट्रस्टी कुशलराज गुलेच्छा ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर आचार्यश्री ने कहा कि सुख देने की ताकत पैसों में नहीं है लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम पैसों और सम्पत्ति से ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। ङ्कङ्कउन्होंने कहा, पैसों से भी सत्ता का प्रभाव ज्यादा है। सत्ता से ज्यादा ताकत प्रसिद्धि की है और प्रसिद्धि से भी ज्यादा प्रभावक मणिमंत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली पुण्य होता है। पुण्य से ही पूरे संसार की और आध्यात्मिक ताकत प्राप्त हो सकती है। आत्मा की पवित्रता की पराकाष्ठा से ही पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मिल सकती है और आत्मा की पवित्रता हमें जिनालयों से ही प्राप्त हो सकती है। ङ्कङ्कपंडित महाराज जी ने कह, परमात्मा की प्रतिमा में अंजनशलाका द्वारा पवित्रता का आरोपण होता है और उसी के शुद्ध भावों से दर्शन करने से हमारी आत्मा भी पवित्र होती है। इस दुनिया में किसी को भी पुण्य प्राप्त करना है तो निस्वार्थ भाव से परोपकार करने से ही पुण्य प्राप्त हो सकता है। बिना परोपकार के पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता है। पुण्य का बंध सुकृत से ही हो सकता है। पवित्रता प्राप्त करने के लिए आत्मा की निर्मलता आवश्यक है। ङ्कङ्कसंतश्री ने कहा, परमात्मा के दर्शन से हमें निर्मलता प्राप्त होती है। मन की निर्मलता और आत्मा की स्वच्छता के लिए जिनालय बहुत जरूरी है। जीने के लिए जिस तरह हमें ताजी हवा चाहिए उसी तरह मन्दिरों की पवित्रता से हमारा मन भी ताजा और प्रफुल्लित हो जाता है।ङ्क ङ्कप्रवचन से पहले जैन कॉलेज से शोभायात्रा के साथ संत व प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाओं का मंगल प्रवेश करवाया गया। विधि विधान रोहित गुरु ने करवाया। परमात्मा के माता पिता बनने का लाभ किशोर जैन, इन्द्र महाराज बनने का लाभ कुशलराज गुलेच्छा को मिला। इस अवसर पर शांतिबाई साकरिया, शांतिलाल नागौरी, बाबूभाई मेहता, राजू सुजानी, नेमीचंद रांका, राजू हिरानी के साथ अनेक ट्रस्टीगण, समिति के अरविन्द कोठारी, ललित डाकलिया, श्रीपाल दांतेवाड़िया , हितेश गुलेच्छा, विकास मेहता और अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे।

महासभा संगठन यात्रा आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के पदाधिकारी 'महासभा आपके द्वार' संगठन यात्रा के अंतर्गत सोमवार को तेरापंथ भवन यशवंतपुर में साध्वी पावनप्रभाजी के सान्निध्य में महासभा शीर्ष मंडल और यशवंतपुर सभा के पदाधिकारियों की गोष्ठी आयोजित हुई। महासभा के उपाध्यक्ष प्रकाश लोढ़ा ने कहा कि यशवंतपुर सभा एक जागरूक एवं सक्रिय सभा है। उन्होंने आवश्यकतानुसार सभा संचालन के लिए सभा निर्देशिका एवं श्रावक सन्देशिका पुस्तक का उपयोग करने का निवेदन किया। दक्षिणांचल मलनाड़ के आंचलिक प्रभारी महेंद्र दक ने महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। सभा प्रभारी नवनीत मूथा ने सभा मूल्यांकन पत्र भरवाया व आगामी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन में पदाधिकारियों की सहभागिता पर जोर दिया।

तेरापंथ महिला मंडल हनुमंतनगर ने आयोजित किया 'श्री उत्सव'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तेरापंथ महिला मंडल, हनुमंतनगर द्वारा 'श्री उत्सव-एक कदम स्वावलंबन की ओर' का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट स्वर्णमाला पोकरना, राष्ट्रीय सह मंत्री मधु कटारिया एवं शशिकला नाहर द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मंडल की अध्यक्षा संगीता तातेड़ ने सभी का स्वागत किया।

मंडल द्वारा पहली बार आयोजित इस प्रदर्शनी में 40 आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें सलवार शूट, साड़ियाँ, ज्वेलरी, हस्तनिर्मित एवं हस्तशिल्प उत्पाद, गृह उपयोगी वस्तुएँ, बेकरी आइटम, उपहार सामग्री तथा अन्य अनेक आकर्षक उत्पाद उपलब्ध थे।

विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

शिष्टाचार भेंट

बेंगलूरु के शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील शर्मा ने मंगलवार को बेंगलूरु पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। शर्मा ने आयुक्त को सम्मान स्वरूप एक पौधा भेंट किया। इस मौके विप्र फाउंडेशन के सदस्य शिव शर्मा भी उपस्थित थे।

निर्माणाधीन सालासर मंदिर में संगीतमय सुन्दरकाण्ड सम्पन्न

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के बन्नरघट्टा रोड रांका कॉलोनी स्थित निर्माणधीन सालासर बालाजी मन्दिर पर पूर्णिमा के अवसर पर सालासर सेवा समिति के तत्वावधान में संगीतमय सुन्दरकाण्ड का आयोजन हुआ जिसमें प्रायोजक ललित भौतिका परिवार ने पूजा की। तत्पश्चात नारायण बाहेती की टीम ने संगीतमय सुन्दरकाण्ड पाठ का वाचन किया जिसमें बडी संख्या में भक्तों ने सामूहिक सुंदरकांड का वाचन किया।

नि:शुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर में 982 लोग हुए लाभान्वित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चित्रदुर्गा। शहर के बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जैन संघ, चित्रदुर्ग, रोटरी बेंगलूरु इंदिरानगर के संयुक्त तत्वावधान में डॉ. सोलंकी आई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ नरपत सोलंकी की 21 सदस्यीय चिकित्सकीय टीम के सहयोग से नि:शुल्क मेगा नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन हुआ।

प्रदीप कुमार धर परमार परिवार के सौजन्य से आयोजित इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक केसी वीरेंद्र पाप्पी व डॉ. एम. चंद्रशेखर द्वारा किया गया। शिविर के दौरान कुल 982 रोगियों की जांच की गई, 190 रोगियों को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चुना गया। इनमें से 145 सर्जरी प्रोजेक्ट दृष्टि और जैन मिशन अस्पताल, चिक्कबलापुर में की गई। डॉ. सोलंकी ने अतिथियों का सम्मान किया।

जीतो नार्थ लेडीज़ विंग ने किया औद्योगिक एवं आध्यात्मिक भ्रमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) नॉर्थ लेडीज विंग द्वारा इंडस्ट्रियल विजिट-जर्नी ऑफ लर्निंग एंड सेरेनिटी के अंतर्गत मंगलवार को औद्योगिक एवं आध्यात्मिक भ्रमण में 80 से अधिक सदस्याओं ने भाग लिया। नॉर्थ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना ने सभी का स्वागत किया। महामंत्री रक्षा छाजेड़ ने औद्योगिक भ्रमण के उद्देश्य तथा उद्यमशीलता की यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। संयोजिका प्रेमा रांका, सह-संयोजिका कला लूनावत के नेतृत्व में सदस्याओं ने नम्मुरा होटल का दौरा किया तथा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ग्राहक सेवा तथा एक सफल होटल संचालन की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।

आध्यात्मिक भ्रमण के तहत सदस्याओं ने कनकपुरा रोड स्थित श्रीश्री रविशंकर आश्रम का दौरा किया तथा विशालाक्षी मंडप, लोटस ध्यान केंद्र एवं मंदिरों का दर्शन किए साथ ही आश्रम स्थित गौशाला का भ्रमण किया। कार्यक्रम में मेंटर रेशमा पुनमिया, उपाध्यक्ष सुमन वेदमुथा सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित थीं।

धर्मांतरण को रोकने की बननी चाहिएं ठोस योजनाएं : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देवरकदरा (तेलंगाना)। देवरकदरा तहसील मुख्यालय पर रेड्डी हाउस में विविध हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि धर्मस्थानों के नवनिर्माण और धर्म के विधि-विधानों से पहले लोगों की धर्मश्रद्धा मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। विचारधारा ही कमजोर रही तो बालक-बालिकाओं तथा युवक-युवतियों को बदलने से हम रोक नहीं पाएंगे। जिनके विचार कमजोर होते हैं, उन्हें कोई भी बहका सकता है, किसी भी मोड़ पर उसकी जिंदगी बदल सकती है, बिखर सकती है। देश में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग में प्रतिवर्ष लाखों लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। पिछले दस वर्षों में जैन समाज में भी धर्मांतरण की सैकड़ों घटनाएं बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बदलते युगीन परिवेश में धर्म के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना और धर्मांतरण को रोकना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब समाज की नई पीढ़ी की धर्मश्रद्धा डगमगा रही है। जगह-जगह धर्मांतरण हो रहा है।

नित नयी लव जिहाद की घटनाएं बन रही हैं। इन सबको रोकने के समुचित रास्ते खोजकर, समाज और अभिभावकों को योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।ङ्कआचार्य विमलसागरसूरीश्वर ने कहा, अब घर-घर मे ज्ञान और सिद्धांतों की अलख जगानी चाहिए। समाज के प्रबुद्धजनों और परिवार के अभिभावकों को इस कार्य के लिए समय और श्रमदान करना चाहिए।

पंड्या ने बेंगलूरु में रहने का फैसला किया

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाया

नई दिल्ली/बेंगलूरु/दक्षिण भारत । स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने करियर के बाकी समय के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को अपना स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने के मकसद से बेंगलूरु में रहने का फैसला किया है और वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रमुख मौजूदा क्रिकेटर बन गए हैं। पंड्या का यह कदम इसलिए सभी का ध्यान खींच रहा है क्योंकि भारत के केंद्रीय अनुंधित खिलाड़ी आम तौर पर चोट से उबरने (रिहैबिलिटेशन), फिटनेस परीक्षण या राष्ट्रीय शिविर के लिए ही सीओई जाते हैं।

पंड्या मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने पिछले दशक में अधिकतर समय मुंबई में बिताया है और मुख्य रूप से अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियन्स की घंसोली स्थित सुविधा में ट्रेनिंग की है। अभी जांघ की चोट से उबर रहे 32 वर्षीय पंड्या ब्रिटेन के सीमित ओवरों के मौजूदा दौरे से बाहर हो गए थे। उन्होंने पिछले छह महीने में सीओई में काफी समय बिताया है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करन की शर्त पर पीटीआई को बताया, हार्दिक पहले ही स्थायी रूप से बेंगलूरु स्थानांतरित हो चुके हैं। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में सीओई के पास एक संपत्ति किराए पर ली है। वह अपने करियर के बाकी समय के लिए सीओई को अपना स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे। सूत्र ने कहा, ''हार्दिक मुंबई से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि ट्रेनिंग के लिए रोजाना अपने लोअर परेल स्थित घर से आना-जाना एक समस्या बन गई थी। केंद्रीय अनुबंध वाले क्रिकेटर के तौर पर उन्हें सीओई में चोट के इलाज से लेकर कौशल ट्रेनिंग तक सभी सुविधाएं मिलेंगी।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए जब भी वह आईपीएल, राज्य या राष्ट्रीय टीम के साथ नहीं हों तो उन्होंने सीओई को अपना स्थायी आधार बनाने का फैसला किया है।'' माना जा रहा है कि हार्दिक के पास अपने फिजियोथेरेपिस्ट और निजी स्ट्रेंथ एवं अनुकूलन कोच भी होंगे जो सीओई के बाहर ट्रेनिंग में उनकी मदद करेंगे। सूत्र ने कहा, ''यह जब तक वह भारत के लिए सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलते हैं तब तक बेंगलूरु में बसने जैसा है और उनका इरादा कम से कम अगले पांच से छह साल तक खेलने का है।''

जीतो स्वयं-वी प्रेन्योर्स की बैठक आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) साउथ लेडीज़ विंग के नेटवर्किंग समूह जेबीएन स्वयं वीप्रेन्योर्स की बैठक जीतो कार्यालय में हुई। बैठक की शुरुआत में सदस्याओं ने व्यवसाय की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर इमेज कंसल्टेंट एवं स्टाइलिस्ट केजल छाजेड़ ने व्यक्तित्व निर्माण, सही बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, प्रभावी आई कॉन्टैक्ट, मजबूत हैंडशेक तथा प्रोफेशनल छवि के निर्माण से जुड़े अनेक तत्थों की जानकारी दी।

साउथ की चेयरपर्सन बबीता रायसोनी एवं मुख्य सचिव निधि पालरेचा ने शुभकामनाएं दी। बैठक में कुल 27 सदस्याएं उपस्थित थीं।

तटरक्षक बल ने कर्नाटक तट के पास भारतीय नौका के छह सदस्यीय चालक दल को बचाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/मंगलूरु। कर्नाटक तट के पास चुनौतीपूर्ण समुद्री खोज एवं बचाव अभियान के दौरान भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने छह मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। उनकी मछली पकड़ने वाली नौका समुद्र में खराब हालात के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें पानी भर गया था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समुद्र की बेहद मुश्किल परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ''रिमोट-संचालित लाइफबॉय'' की मदद से भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका 'मंजू माता' के सभी छह चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया।

आईसीजी के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार शाम को तटरक्षक बल के 'जहाज सचेत' को कर्नाटक के सूरतकल तट से लगभग 33 समुद्री मील दूर एक मछली पकड़ने वाली नौका से मदद का फोन कॉल आया। नौका पर सवार लोगों ने बताया कि समुद्र में खराब हालात की वजह से नौका में बहुत अधिक पानी भर गया है और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नौका पर मौजूद सभी छह चालक दल के सदस्यों की जान को तुरंत खतरा पैदा हो गया है। अधिकारी ने कहा, ''आईसीजी ने बिना देर किए मदद के लिए जहाज को संकटग्रस्त नौका की दिशा में मोड़ा और 90 मिनट के अंदर ही मुसीबत में फंसी नौका तक पहुंच गया।'' यह बचाव अभियान बहुत चुनौतीपूर्ण मौसमी परिस्थितियों में चलाया गया।

प्रवक्ता ने कहा, ''समुद्र में तूफान, तेज हवाएं, कम दृश्यता और अंधेरा होने की वजह से अभियान बहुत जटिल हो गया था। इसके लिए बचाव दल को बेहतरीन समुद्री कौशल, सटीकता और तालमेल की जरूरत होती है।'' तटरक्षक ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद आईसीजी की टीम ने ''बेहतरीन कुशलता'' के साथ अभियान को अंजाम दिया। प्रवक्ता ने बताया कि असाधारण साहस, पेशेवर तरीके और अभियान के लिए तत्परता दिखाते हुए तटरक्षक बल ने मुसीबत में संकटग्रस्त नौका से छह मछुआरों को बचाया।आईसीजी ने कहा, ''टीम ने खराब समुद्री हालात में इस्तेमाल के लिए खास तौर पर बनाए गए रिमोट संचालित लाइफबॉय' का इस्तेमाल किया ताकि फंसे हुए मछुआरों तक सुरक्षित पहुंचा जा सके और उन्हें बचाया जा सके।'' तटरक्षक बल ने बताया कि देर शाम तक चालक दल के सभी छह सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया जिन्हें कोई चोट नहीं आई थी। प्रवक्ता ने बताया कि आईसीजी का 'जहाज सचेत' अभी न्यू मंगलुरु पहुंच रहा है ताकि बचाए गए चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतारा जा सके और आगे की औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। अधिकारी ने बताया कि 'मंजू माता' नौका 2019 में बनाई गई थी और कर्नाटक के उडुपी में पंजीकृत थी। इसका ढांचा फाइबर ग्लास से बना था।

स्वागत

मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार को 'कैंसर हीलर सेंटर' की एक नई शाखा के उद्घाटन के दौरान आध्यात्मिक गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**